बैंक नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति
जयपुर

बैंक ज्योति

जुलाई – दिसंबर 2025

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर
छमाही पत्रिका

हिंदी दिवस एवं पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

दिनांक 14 सितंबर, 2025 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस एवं पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रथम दिवस में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), जयपुर को 'नराकास सम्मान' के तहत अखिल भारत स्तर पर 'तृतीय पुरस्कार' प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में समिति की ओर से यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के कर कमलों से महाप्रबंधक (जयपुर अंचल) एवं नराकास अध्यक्ष श्री एम. अनिल ने प्राप्त किया। इस अवसर पर सांसद, राज्यसभा श्री दिनेश शर्मा, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, श्रीमती अंशुली आर्या, वैज्ञानिक एवं लेखक डॉ. आनंद रंगनाथन भी उपस्थित रहे।

'जलवायु जोखिम प्रबंधन – वित्तपोषण एवं बीमा' विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर द्वारा 'जलवायु जोखिम प्रबंधन–वित्तपोषण एवं बीमा' विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान स्थित भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यरत बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। तीन सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित प्रतिभागियों द्वारा बारी–बारी से प्रस्तुति दी गई तथा इन सत्रों की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक श्री राजेश सिंह, बैंक के उप महाप्रबंधक (एसएलबीसी) श्री राज कुमार मीना, सहायक महाप्रबंधक श्री अनुज अवस्थी एवं श्री अमित कुमार तिवारी तथा अन्य कार्यपालकों ने की।

नराकास, जयपुर की 80वीं छमाही बैठक आयोजित

दिनांक 29 अगस्त, 2025 को नराकास, जयपुर की 80वीं बैठक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री एम. अनिल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नराकास, जयपुर के सदस्य कार्यालयों द्वारा पिछले छः माह में राजभाषा संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री नवीन नंबियार विशिष्ट अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए तथा नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर रवि बाबू ऑनलाइन रूप से जुड़े। इस आयोजन में समिति की पत्रिका 'बैंक ज्योति' का भी विमोचन किया गया।

बैंक नराकास, जयपुर की छमाही पत्रिका

बैंक ज्योति

जुलाई-दिसंबर, 2025

अध्यक्ष :
एम. अनिल
महाप्रबंधक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल

उपाध्यक्ष
रुचि शिवलिहा
उप महाप्रबंधक
(अनुपालन एवं आश्वासन)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल

सदस्य सचिव :
अम्ब्रेश रंजन कुमार
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल

संपादन सहयोग
मिथलेश मीणा
प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर

रानू साव
प्रबंधक (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

निशा चोरेटिया
प्रबंधक (राजभाषा)
इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर

संपर्क :
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
नराकास सचिवालय, अंचल कार्यालय, बड़ौदा भवन,
13 एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, जयपुर
दूरभाष : 0141-2727130
ईमेल : rajbhasha.rz@bankofbaroda.bank.in
www.banktolicjaipur.com

इस अंक में

संपादक मंडल एवं अनुक्रमणिका	03
अध्यक्ष की कलम से...	04
उपाध्यक्ष की कलम से....	05
विकसित भारत – 2047 के लक्ष्य.....	6–10
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	11–12
मिशन कर्मयोगी	13–15
हिन्दी : मेरी मातृभाषा	16
रिक्शेवाला	16
जी करता है	17
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	18–21
बढ़ता शहरीकरण एवं निम्न.....	22–27
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	28–32
मेरी पसंदीदा पुस्तक	33–34
मैं नारी हूँ	35
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	35–37
सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी	38–39
बैंक नराकास जयपुर के सदस्य कार्यालय	40

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त लेखकों के विचारों से समिति का सहमत होना जरूरी नहीं है।

अम्ब्रेश रंजन कुमार, सदस्य सचिव, बैंक नराकास, जयपुर एवं मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित एवं अशोका ऑफसेट, जयपुर द्वारा मुद्रित (केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

अध्यक्ष की कलम से...

प्रिय पाठको,

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की पत्रिका 'बैंक ज्योति' के माध्यम से आप सभी से संवाद करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। यह पत्रिका न केवल विचारों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों का संकलन है, बल्कि हमारी समिति की वैचारिक चेतना, भाषायी प्रतिबद्धता और सेवा–भावना का भी प्रतिबिंब है।

हम वित्तीय लेन–देन तथा बीमा सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम होने के साथ–साथ जन–संपर्क, विश्वास और सेवा का भी एक सशक्त माध्यम हैं। ऐसे समय में, जब बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र निरंतर तकनीकी नवाचार, प्रतिस्पर्धा और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के दौर से गुजर रहा है, भाषा की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समूचे तंत्र में भाषा, विशेषकर राजभाषा हिंदी, सेतु का कार्य करती है। हिंदी हमारी संवैधानिक पहचान होने के साथ–साथ आम जन से सीधे जुड़ने का सबसे प्रभावी और आत्मीय माध्यम है। जब हमारा कार्य–व्यवहार, पत्राचार और संवाद जनभाषा में होता है, तब ग्राहक स्वयं को अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करता है।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के सभी सदस्य कार्यालय संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। भारत सरकार ने भी हमारी इस प्रतिबद्धता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 'नराकास सम्मान' प्रदान कर हमें सम्मानित किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने हमारी समिति को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ समितियों की सूची में शामिल किया है। यह समिति द्वारा ली गई विविध एवं विलक्षण पहलों के कारण ही संभव हो सका है। मैं इस उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं।

हमें यह दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि हिंदी का प्रयोग केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं, बल्कि एक सशक्त अवसर है– ग्राहकों तक सरल, स्पष्ट और संवेदनशील ढंग से पहुँचने का अवसर। आंतरिक संचार, प्रशिक्षण, प्रशासनिक कार्यों से लेकर ग्राहक सेवा तक हिंदी का प्रभावी उपयोग बैंकिंग को अधिक समावेशी, मानवीय और उत्तरदायी बनाता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है कि– **"जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।"**

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'बैंक ज्योति' पत्रिका एक सशक्त और सार्थक मंच के रूप में हमारे समक्ष है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के इस प्रयास से राजभाषा हिंदी को सदस्य कार्यालयों के दैनिक कार्य–व्यवहार में और अधिक प्रभावी और सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। मैं इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी सहयोगियों, प्रकाशन उप समिति एवं संपादकीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है कि 'बैंक ज्योति' हिंदी के माध्यम से सेवा, संवेदना, समर्पण और नवाचार की भावना को और अधिक सशक्त करते हुए हम सभी को अपने कार्य–दायित्वों के प्रति अभिप्रेरित करती रहेगी।

(एम. अनिल)
महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष
बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर

उपाध्यक्ष की कलम से...

प्रिय पाठको,

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की पत्रिका 'बैंक ज्योति' के नवीनतम अंक के माध्यम से आप सभी से जुड़ना मेरे लिए विशेष है। यह पत्रिका न केवल राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार का सशक्त मंच है, बल्कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की वैचारिक दिशा और कार्य–संस्कृति का भी दर्पण है। आज के बदलते परिवेश में भाषा, व्यवसाय और जीवन–शैली–तीनों एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और 'बैंक ज्योति' इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में पिरोने का सार्थक प्रयास है।

प्रशासनिक व्यवस्था में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रशासन और नागरिकों के बीच पारदर्शिता और सहभागिता की नींव रखती है। सरल, सुस्पष्ट और सर्वग्राही भाषा नीतियों, योजनाओं और निर्णयों को जन–जन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बनती है। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो व्यवसाय वृद्धि सीधे तौर पर भाषा से जुड़ी हुई है। पेशेवर जीवन में सरल भाषा को अपनाने से न केवल कारोबार का विस्तार होता है, बल्कि संस्था विशेष की सामाजिक छवि भी सुदृढ़ होती है।

आज कार्यालयी कार्य, केवल कार्य–दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन–शैली बन चुका है। लक्ष्य आधारित कार्य–संस्कृति, तकनीकी बदलाव, समय–सीमा का दबाव और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएँ कर्मचारियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में संतुलित जीवन–शैली और सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक स्वस्थ जीवन–शैली ही दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता की आधारशिला होती है।

रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं कि– **मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।**

किन्तु वही मानव कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने मानसिक संबल खोकर हार मान लेता है। वर्तमान परिदृश्य में सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से स्वस्थ कर्मचारी ही बेहतर निर्णय ले सकता है, तनावपूर्ण परिस्थितियों का समाधान कर सकता है और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है।

यही वजह है कि अब संस्थानों में भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने को भी प्राथमिकता दी जाने लगी है। कार्यालय अब ना केवल व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, बल्कि अपने मानव संसाधन के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। यह पहल कर्मचारियों को यह संदेश देती है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और आत्म–सम्मान का प्रतीक है। संवहनीय विकास के लिए ऐसी पहलें अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से संवहनीय विकास में भाषाओं की भूमिका भी अहम है।

'बैंक ज्योति' पत्रिका इन सभी विषयों–राजभाषा, व्यवसाय और जीवन–शैली को एक साझा मंच प्रदान करती है। यह मंच विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों से जुड़ी आवाज़ों को एक साथ लाकर आपसी समझ, सहयोग और संवाद को सशक्त बनाता है। इसके माध्यम से राजभाषा के प्रयोग को केवल औपचारिक दायरे तक सीमित न रखकर उसे व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे संगठन में विचारों का मुक्त प्रवाह और बौद्धिक चेतना का विस्तार होता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'बैंक ज्योति' भविष्य में भी हमें भाषा के प्रति संवेदनशील, व्यवसाय के प्रति सजग और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मैं इस पत्रिका से जुड़े सभी सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि यह पत्रिका हम सभी के लिए प्रेरणा, संवाद और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनी रहेगी।

रुचि शिवलिहा
उप महाप्रबंधक एवं उपाध्यक्ष
बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्वोत्तर भारत की भूमिका

प्रस्तावना

विकसित भारत 2047 भारत का वह व्यापक लक्ष्य है जिसमें आर्थिक शक्ति, सामाजिक समावेशन, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन का सम्मिश्रण कर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। यह केवल सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी नहीं बल्कि जनसाधारण के दैनिक अनुभव में सुधार का कार्यक्रम है। एक आधिकारिक मार्गदर्शिका में यह कहा गया कि Ease of Living हर नागरिक का अधिकार है और इसलिए प्राथमिकता प्रक्रियाओं को सरल, तकनीक समर्थ और नागरिक प्रथम बनाना है। यह कथन प्रशासन की नई संस्कृति को रेखांकित करता है जिसमें नीति से लेकर क्रियान्वयन तक पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो रही है।

यह लेख उसी व्यापक लक्ष्य को पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में समझाता है। संरचना क्रमशः अवधारणाओं और परिभाषाओं का स्पष्टीकरण, पूर्वोत्तर की सामरिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सुधार कार्यक्रमों का विस्तृत विवेचन, संसाधन आधारित योगदान का विश्लेषण, शांति और सुरक्षा संबंधी प्रसंग, तथा 2047 तक के लिए प्राथमिकताओं की रूपरेखा पर आधारित है। प्रस्तुत तथ्य नीति आयोग के कार्यपत्रों, प्रशासनिक सुधार विषयक संकलनों तथा प्रेस सूचना ब्यूरो, विकास मंत्रालय उत्तर पूर्व, सड़क परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड और अन्य आधिकारिक स्रोतों पर अधारित हैं।

विकसित भारत 2047 की अवधारणा और परिभाषाएँ

परिभाषा विकसित भारत 2047 केन्द्र सरकार की वह दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि है जिसके अनुसार भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच जाएगा। इस लक्ष्य में आर्थिक समृद्धि के साथ मानव विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, कौशल और उत्पादक रोजगार, उन्नत बुनियादी ढांचा, अनुसंधान एवं नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और प्रभावी सुशासन सम्मिलित हैं। नीति आयोग के वैचारिक दस्तावेजों में यह लक्ष्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आयामों में व्यक्त हुआ है।

परिभाषा विकसित राष्ट्र की कोई सर्वमान्य विधिक परिभाषा नहीं है, किंतु सामान्यतः वह देश विकसित माना जाता है जहां प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, मानव विकास सूचकांक में सतत् सुधार हो, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र उन्नत हों, अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश हो, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना सक्षम हो और न्याय तथा सुशासन की व्यवस्था विश्वास उत्पन्न करे। एक प्रशासनिक संकलन में कहा गया कि उत्तम शासन वही है जो सहभागी, पारदर्शी, जवाबदेह, दक्ष, समतामूलक हो और कानून के राज का पालन करे, तथा जिसका अंतिम लक्ष्य नागरिक की जीवन गुणवत्ता हो। यह उद्धरण विकसित भारत के सुशासन आयाम को स्पष्ट करता है।

संकेतक लक्ष्य के रूप में अनेक परामर्श रिपोर्टों में 2047 तक तीस से चालीस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद, पंद्रह से बीस हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय, अनुसंधान निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के ढाई प्रतिशत तक ले जाने और सन् 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन जैसे मान प्रस्तुत किए गए हैं। यह भी रेखांकित किया गया है कि अगले दो दशकों में पूंजीगत निवेश, विनिर्माण, कौशल, शहरीकरण और कनेक्टिविटी में बड़े सुधार अनिवार्य होंगे।

चार स्तंभों का सिद्धान्त विकसित भारत की सामाजिक वास्तु को परिभाषित करता है। युवा, गरीब, महिलाएँ और अन्नदाता ये चार आधार स्तंभ हैं। एक मिशन वक्तव्य में यह भी कहा गया कि शून्य गरीबी, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और स्वास्थ्य, सौ प्रतिशत कुशल श्रम बल, महिला की आर्थिक भागीदारी का विस्तार और किसानों द्वारा भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाना इस दृष्टि का सामाजिक अनुबंध है। यह उद्धरण स्पष्ट करता है कि विकसित भारत का लक्ष्य समावेशी समाज पर आधारित है।

पूर्वोत्तर भारत का परिप्रेक्ष्य और महत्ता

भौगोलिक और सामरिक स्थिति के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर क्षेत्र असाधारण है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा मिलकर भारत के कुल भूभाग का लगभग आठ प्रतिशत और जनसंख्या का लगभग चार प्रतिशत हैं। यह क्षेत्र चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगभग पाँच हजार किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है। शेष भारत से भूमि संपर्क का मुख्य गलियारा सिलिगुड़ी कॉरिडोर है। यही कारण है कि यह क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति का वास्तविक द्वार बनता है और आसियान देशों तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हमारे संपर्क का अग्रिम पथ है।

सांस्कृतिक और सामाजिक संपदा की दृष्टि से पूर्वोत्तर अद्वितीय है। यहाँ अनेक जनजातीय और भाषाई समुदाय हैं, साक्षरता के मानक देश के औसत से कई बार बेहतर मिलते हैं और सामुदायिक संस्थाएँ सार्वजनिक जीवन को दिशा देती हैं। आर्थिक संरचना में कृषि और बागवनी, वन आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प और हैंडलूम, चाय और तेल गैस जैसे संसाधनों की उपस्थिति रही है। यह विविधता नीति डिजाइन में स्थानीय अनुकूलन, समुदाय सहभागिता और लाभ साझेदारी को अनिवार्य बनाती है ताकि विकास की योजनाएँ सामाजिक स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ें।

शांति समावेशन और सुरक्षा का परिदृश्य

विकास का आधार स्थिरता है और स्थिरता का आधार शांति है। पिछले दशक में किए गए शांति समझौते और विधिक व्यवस्थाओं में विवेकपूर्ण परिवर्तन ने पूर्वोत्तर के सुरक्षा वातावरण को बेहतर बनाया है। बोड़ो क्षेत्रीय समझौता, करबी आंगलांग समझौता, असम मेघालय सीमा समझौता, तथा उग्रवादी संगठनों के साथ किए गए नए समझौते इसके उदाहरण हैं। प्रभाव यह हुआ कि हिंसा की घटनाएँ और हताहत घटे, आमजन का विश्वास बढ़ा और निवेश वातावरण में सुधार आया। यह अनुभव दर्शाता है कि विकास और शांति एक दूसरे के पूरक हैं।

वित्तपोषण और कार्यक्रमगत ढाँचा

दस प्रतिशत जी बी एस नीति के अंतर्गत 2014 पंद्रह से 2024 पच्चीस के बीच केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल पाँच लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ पूर्वोत्तर तक लक्षित रूप से पहुँचे और क्षेत्रीय असमानता घटे।

विकास मंत्रालय उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व परिषद की योजनाओं के तहत इकतीस दिसंबर 2025 तक कुल तीन हजार छह सौ उन्नहत्तर परियोजनाएँ स्वीकृत अथवा प्रगति पर थी जिनकी स्वीकृत लागत लगभग अड़तालीस हजार दो सौ तिहत्तर करोड़ रुपये है। डिजिटल डैशबोर्ड पर परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति, भू टैगिंग और उपयोग प्रमाण पत्र का संकलन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करते हैं।

प्रधानमंत्री विकास पहल उत्तर पूर्व यानी पीएम डिवाइन दो हजार बाईस ते छब्बीस के बीच छह हजार छह सौ करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में कैंसर देखभाल, शिक्षा और कौशल, पर्यावरण अनुकूल रोपवे, जल आपूर्ति तथा सड़क और नगरीय अवसंरचना जैसी परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं। यह योजना उन सेक्टरों में पूरक वित्तपोषण देती है जहाँ अन्य योजनाएँ पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच रहीं।

भौतिक कनेक्टिविटी सड़क रेल हवाई और जलमार्ग

सड़क अवसंरचना में भारतमाला परियोजना के तहत आर्थिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर, सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी और द्रुत मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और निर्माण गति में वृद्धि से लॉजिस्टिक्स दक्षता के संकेतक बेहतर हुए हैं। विशेष तौर पर पूर्वोत्तर में एस ए आर डी पी एन ई और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के संयोजन से दुर्गम जिलों तक पहुँच सरल हुई है और सीमावर्ती व्यापार तथा पर्यटन को बल मिला है।

रेल संपर्क में दो हजार चौबीस पच्चीस तक अठारह परियोजनाएँ लगभग तेरह सौ अड़सठ किलोमीटर के परिमाण में विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से लगभग तीन सौ तेरह किलोमीटर कमीशंड हो चुके हैं। कठिन भूभाग में सुरंगों और पुलों का निर्माण, नई लाइनों का विकास और राजधानियों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास क्षेत्रीय एकीकरण में मील का पत्थर हैं।

हवाई संपर्क में उडान योजना ने परिवर्तनकारी भूमिका निभायी है। पूर्वोत्तर में नब्बे से अधिक मार्ग और बारह से अधिक हवाई अड्डे तथा हेलीपोर्ट सक्रिय हैं। दो हजार बीस इक्कीस से दो हजार बाइस तेईस के बीच गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, सिलचर, दीमापुर और अगरतला जैसे केंद्रों पर विमान आवागमन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। यह कनेक्टिविटी न केवल पर्यटकों और व्यापारियों के लिए बल्कि आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा आपात स्थितियों में भी निर्णायक सिद्ध हो रही है।

जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, फेरी और बहु माध्यमीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। बड़े और भारयुक्त माल के लिए यह किफायती विकल्प प्रदान करते हैं जिससे सीमावर्ती जिलों में आजीविका के अवसर उत्पन्न होते हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी और ई–शासन

भारतनेट परियोजना ने ग्राम पंचायत स्तर तक ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट पहुँच सुनिश्चित करनी शुरू की है। जुलाई दो हजार चौबीस तक दो लाख तेरह हजार से अधिक ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार थीं, लगभग छह लाख नवासी हजार किलोमीटर ओ एफ सी बिछ चुकी थी, दस लाख छप्पन हजार से अधिक एफ टी टी एच कनेक्शन चालू और एक लाख चार हजार से अधिक वाई फाई हॉटस्पॉट स्थापित थे। यह आधार ग्रामीण ई हेल्थ, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस के लिए परिवर्तनकारी है।

यूनिवर्सल सर्विस फंड और डिजिटल भारत निधि के माध्यम से पूर्वोत्तर के दुर्गम क्षेत्रों में दो हजार आठ सौ से अधिक मोबाइल टावर कमीशंड हुए जिससे कई हजार गाँव पहली बार चौथी पीढ़ी की डाटा सेवाओं से जुड़े। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सेवा वितरण को पारदर्शी बनाते हुए नागरिक के विश्वास को सुदृढ़ किया। यह परिवर्तन केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि न्यायसंगत पहुँच और पारदर्शी सेवाओं का नया सामाजिक अनुबंध है।

कृषि बागवनी बाँस और वनाधारित अर्थव्यवस्था

पूर्वोत्तर की ऊँचाई, वर्षा और मृदा विविधता के कारण यहाँ मसाले जैसे अदरक हल्दी मिर्च, फल फूल जैसे संतरा अनानास कीवी, ऑर्थोडॉक्स चाय, औषधीय और सुगंधित पौधे तथा बाँस की प्रचुरता है। राष्ट्रीय स्तर पर बागवनी का कृषि सकल मूल्य वर्धन में लगभग तैंतीस प्रतिशत योगदान है और हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड के माध्यम से नब्बे प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध है। इससे हॉर्टीकल्चर क्लस्टर, पश्च फसल प्रबंधन और कोल्ड चेन का विकास संभव हुआ है।

बाँस के संदर्भ में उत्तर पूर्व परिषद की कार्ययोजना बाँस प्रसंस्करण क्षेत्र, मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और उद्यमिता वित्त जैसे उपायों का प्रस्ताव करती है। इससे फर्नीचर, इंजीनियर्ड बोर्ड, फर्श सामग्री, बायोचार, फाइबर कंपोजिट और हरित निर्माण सामग्री की मूल्य शृंखलाएँ विकसित हो सकती हैं। यह केवल उद्योग नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़े शिल्प और आजीविका का भी संवर्द्धन है। एक उद्धरण में यह विचार व्यक्त हुआ कि बाँस केवल कच्चा माल नहीं बल्कि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है और इसे उद्योग नीति, नवाचार और निर्यात मानकों से जोड़ना समय की मांग है।

नीतिगत समर्थन की दृष्टि से पीएम एफ एम ई यानी पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एफ पी ओ गठन और प्रोत्साहन, पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाएँ मिलकर क्लस्टर आधारित कृषि उद्यमिता को गति देती हैं। इससे उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार तक पहुँच तीनों में सुधार संभव होता है।

औद्योगिक विकास, एम एस एम ई और निवेश प्रोत्साहन

उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत पूंजी व्यय प्रोत्साहन, ब्याज सबवेंशन, बीमा और परिवहन प्रतिपूर्ति जैसे लाभ उपलब्ध हैं जिनसे एग्रो प्रोसेसिंग, बाँस और हस्तशिल्प, पर्यटन और आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, ई कॉमर्स पूर्ति और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने का आकर्षण बढ़ा है। खुले सरकारी डाटा और परियोजना डैशबोर्ड उच्च मूल्य परियोजनाओं की जानकारी को सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और नीति निर्माताओं को वास्तविक समय में निर्णय समर्थन प्रदान करते हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारतमाला, बहु माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क, अंतर्देशीय जलमार्ग और सीमा अवसंरचना पर समवेत निवेश की आवश्यकता है। जब सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग का जोड़ सुदृढ़ होता है तो कुल परिवहन लागत घटती है, आपूर्ति शृंखला विश्वसनीय बनती है और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़ाव बढ़ता है। यह पूर्वोत्तर को क्षेत्रीय निर्यात केंद्र में बदलने का आधार बन सकता है।

एक्ट ईस्ट नीति और सीमापार समेकन

एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है और उत्तर पूर्व को आसियान से भौतिक, डिजिटल और लोगों की आवाजाही के माध्यम से जोड़ना है। कलादान मल्टी मॉडेल ट्रांजिट परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और सीमा हाट जैसे प्रयास इसी दिशा के ठोस कदम हैं। जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, पूर्वोत्तर के कृषि, बागवनी, चाय और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए क्षेत्रीय बाजार खुलते हैं और सीमावर्ती समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सृजित होते हैं।

संसाधन आधारित योगदान का विश्लेषण

पूर्वोत्तर का लगभग सत्तर प्रतिशत भूभाग पहाड़ी और वनाच्छादित है। उच्च वर्षा और नदी घाटियाँ इसे जल विद्युत, बाँस और अन्य वन उत्पाद, बागवनी तथा इको टूरिज्म के लिए उपयुक्त बनाती हैं। डिगबोई में स्थापित भारत का पहला तेल कूप, असम की ऑर्थोडॉक्स चाय और बाँस आधारित कारीगरी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इन परिसंपत्तियों का विवेकपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल दोहन राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात आय में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत सम्भावनाओं का उपयोग न्यायसंगत परिवर्तन के सिद्धान्त के अनुरूप होना चाहिए। इसका अर्थ है कि परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों के हित, पुनर्वास और लाभ साझेदारी, पर्यावरण प्रवाह तथा डाउनस्ट्रीम जोखिम प्रबंधन के साथ समन्वित हों। साथ ही हरित हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा जैसे उभरते अवसरों से इसे जोड़ा जा सकता है ताकि ऊर्जा संक्रमण में पूर्वोत्तर अग्रणी बने।

कृषि बागवनी योगदान में राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड और कृषि मंत्रालय के आँकड़े दर्शाते हैं कि संतरा, अनानास, केला, अदरक, हल्दी, मिर्च और उच्च पर्वतीय कीवी जैसे उत्पादों में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी उल्लेखनीय है। यदि भौगोलिक संकेतक और जैविक प्रमाणन, कोल्ड चेन और ट्रेसेबिलिटी प्रणाली सुदृढ़ हों तो राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में इस हिस्सेदारी को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है।

सुशासन, डाटा आधारित निगरानी और संस्थागत समन्वय

पी एम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने बहु मंत्रालयीय समन्वय, डेटा लेयरों का उपयोग और परियोजना अनुक्रमण के माध्यम से अवसंरचना योजना की गुणवत्ता बढ़ाई है। इससे समय और लागत की बचत, बाधा बिंदुओं की पहचान और अंतिम पायदान तक कनेक्टिविटी सुधार में मदद मिली है। भारत का लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स रैंक भी हाल के वर्षों में बेहतर हुआ है जो इसी समन्वय का साक्ष्य है।

डिजिटल डैशबोर्ड और खुले डाटा जैसे एम डोनर प्रोजेक्ट्स डैशबोर्ड, पूर्वोत्तर विकास सेतु और पी एम गति शक्ति पोर्टल ने वास्तविक समय में मॉनिटरिंग, भू टैगिंग और उपयोग प्रमाण पत्रों की ट्रैकिंग को सरल बनाया है। दो हजार चौबीस में प्रक्रियात्मक सरलीकरण जैसे चार किश्तों में फंड रिलीज और अवधारणा पत्र तथा डी पी आर का संयुक्त अनुमोदन जैसी व्यवस्थाओं ने परियोजना स्वीकृति समय को घटाया है।

चुनौतियाँ और जोखिम शमन

भूभाग, अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन जैसी भौगोलिक चुनौतियाँ निर्माण और रखरखाव की लागत बढ़ाती हैं। डिजिटल विभाजन के कारण कुछ जिलों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल कवरेज का अंतर बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बागवनी और चाय पर महसूस किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी, विघटनकारी गतिविधियाँ और आपदा जोखिम अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। कौशल असंगति और पलायन के कारण स्थानीय उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी महसूस होती है और कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स लागत अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इन जोखिमों का समाधान जलवायु स्मार्ट कृषि, बहु माध्यमीय कनेक्टिविटी, राज्य विशेष कौशल विकास, सीमा प्रबंधन का तकनीकी आधुनिकीकरण और समुदाय आधारित भागीदारी के माध्यम से संभव है।

उदाहरण और घटनाएँ जिनसे पूर्वोत्तर का महत्व स्पष्ट होता है

एक उल्लेखनीय प्रसंग एक्ट ईस्ट नीति का है। त्रिपक्षीय राजमार्ग और सीमा हाट जैसे उपायों ने सीमावर्ती व्यापार के नए द्वार खोले हैं। उत्तर पूर्व के फल मसाले चाय और हस्तशिल्प को अब ऐसे बाजारों तक पहुंच का मार्ग मिलता है जो पहले दूरी और कनेक्टिविटी बाधाओं के कारण उपलब्ध नहीं थे। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल और लोगों से लोगों के संपर्क का भी विस्तार है जिसके दूरगामी लाभ देश के सामरिक हितों तक जाते हैं।

दो हजार सैंतालीस तक की कार्यसूची

प्रथम, क्लस्टर आधारित कृषि, बागवनी और बाँस औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। एफ पी ओ आधारित प्रसंस्करण पार्क, पश्च फसल प्रबंधन और कोल्ड चेन, ई नाम और ओ एन डी सी के माध्यम से बाजार एकीकरण, भौगोलिक संकेतक और जैविक ब्रांडिंग का विस्तार आवश्यक है। द्वितीय, लॉजिस्टिक्स विकास में बहु माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री बंदरगाह संयोजन, गुणवत्ता जाँच और शीतित भंडारण का प्रसार हो। तृतीय, डिजिटल पूर्णता के लिए घर घर फाइबर, चार जी और पाँच जी सैचुरेशन और सरकारी सेवाओं का मोबाइल प्रथम वितरण मॉडल लागू हो। चतुर्थ, पर्यटन संस्कृति और शिल्प के लिए प्रशिक्षित गाइड, सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल, डिजिटल बुकिंग और भुगतान प्रणाली तथा होम स्टे का मानकीकरण किया जाए। पंचम, हरित ऊर्जा और जलविद्युत में न्यायसंगत परिवर्तन, समुदाय लाभ साझेदारी और पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित हो। षष्ठ, शांति और विकास संधि की दृष्टि से शेष सीमावर्ती और सामुदायिक विषयों का संवादपूर्ण समाधान हो। सप्तम, युवा और महिला केंद्रित कौशल तथा स्टार्टअप मिशन के माध्यम से आई टी सेवाएँ, कृषि तकनीक, जैव अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स तकनीक और पर्यटन आतिथ्य में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाए।

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 का स्वप्न पूर्वोत्तर भारत के बिना अधूरा है। इस क्षेत्र को केवल द्वार के रूप में नहीं बल्कि विकास इंजन के रूप में देखने की आवश्यकता है। जब शांति और कनेक्टिविटी स्थिर हो जाती है तो कृषि बागवनी और बाँस की मूल्य शृंखलाएँ, डिजिटल शासन, लॉजिस्टिक्स एकीकरण और मानव पूंजी के स्तंभ मिलकर समग्र विकास को गति देते हैं। यही समन्वित ढाँचा भारत को दो हजार सैंतालीस तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थायी और समावेशी रूप से स्थापित कर सकता है।

राहुल कुमार शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय,
यूको बैंक, जयपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर की गतिविधियाँ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर 'सर्वश्रेष्ठ श्रेणी' में शामिल

दिनांक 15 सितंबर, 2025 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस एवं पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दूसरे दिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर को 'नराकास प्रोत्साहन सम्मान' के तहत अखिल भारत स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ' श्रेणी का पुरस्कार' प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में समिति की ओर से यह पुरस्कार महाप्रबंधक (जयपुर अंचल) एवं नराकास अध्यक्ष श्री एम. अनिल ने प्राप्त किया। इस अवसर पर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग श्रीमती अंशुली आर्या, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. देबदत्त चांद सहित अन्यं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा जयपुर अंचल की पत्रिका का विमोचन

दिनांक 18.11.2025 को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री संजय मुदालियर जयपुर अंचल कार्यालय के दौरे पर रहे। इस दौरान कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा जयपुर अंचल की पत्रिका 'मरु सृजन' के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक, जयपुर अंचल श्री एम. अनिल, उप महाप्रबंधक (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान) श्री राज कुमार मीना, उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) श्री अतुल कुमार कर्ण, उप महाप्रबंधक (अनुपालन एवं आश्वासन) सुश्री रुचि शिवलिहा, उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग) श्री बृज मोहन मीना सहित जयपुर अंचल के सभी क्षेत्रीय प्रमुख, उच्च कार्यपालकगण एवं अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

'बड़ौदा मेधावी विद्यार्थी सम्मान' समारोह का आयोजन

दिनांक 20.12.2025 को अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की मेधावी छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में एम.ए. (हिन्दी) में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 'बड़ौदा मेधावी विद्यार्थी सम्मान' से सम्मानित किया गया। छात्राओं को बैंक की ओर से यह सम्मान बैंक के महाप्रबंधक श्री एम. अनिल एवं उप महाप्रबंधक (अनुपालन एवं आश्वासन) श्रीमती रुचि शिवलिहा ने प्रदान किया।

जयपुर अंचल के स्टाफ सदस्यों के लिए राजभाषा प्रतियोगिता का आयोजन

दिनांक 02.12.2025 को जयपुर अंचल कार्यालय में पदस्थ अलग–अलग वेतनमान के स्टाफ– सदस्यों के लिए राजभाषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को दिनांक 20 दिसंबर 2025 को आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया।

अंचल कार्यालय, यूनियन बैंक, जयपुर की गतिविधियाँ

'हिन्दी दिवस एवं सांस्कृतिक संध्या' का आयोजन

अंचल कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में 'हिन्दी दिवस एवं सांस्कृतिक संध्या' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. अल्पना कटेजा, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर जयपुर अंचल प्रमुख श्री अजय कुमार साथ में उप अंचल प्रमुख एवं अंचल के समस्त क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे।

रिश्ते

कमरे की दराजों में पड़े हुए,
ख़त कुछ मिले यूं मुड़े हुए।
स्याही कुछ धुंधला गई थी,
रिश्ते फिर भी थे जुड़े हुए।

उनके जाने इल्म था यक़ीनन,
फूल मिले आंगन में मुरझे हुए।
रोज की कोशिश टूट ही गई,
जो चेहरों के रंग थे उड़े हुए।

ख्वाहिशें पूरी करने में मारा गया,
पैरों में उसके मोती थे जड़े हुए...

गौरव शर्मा 'कलरव'
प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा
अंचल कार्यालय

मिशन कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की दिशा में सहयोगात्मक, संयुक्त प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों को और सशक्त करना है।

सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन. पी. सी. एस. सी. बी.)–मिशन कर्मयोगी एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित एक सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है। यह मिशन भारत की प्राथमिकताओं की साझा समझ पर जोर देता है, जिसमें सिविल सेवक प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव से काम कर रहे हैं।

मिशन कर्मयोगी गतिशील वातावरण में फलने–फूलने के लिए सिविल सेवा को सशक्त बनाने, शासन की विकसित जरूरतों को पूरा करने और सरकार–नागरिक बातचीत को बढ़ाने पर केंद्रित है। सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करके, यह मिशन 2047 तक विकसित भारत की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है।

कर्मयोगी प्रशिक्षण का महत्व यह है कि यह **'विकसित भारत–2047'** के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, तथा सिविल सेवकों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाकर सरकारी कार्यप्रणाली को सक्षम और कुशल बनाता है, जिससे राष्ट्र के विकास में तेजी आती है. iGOT कर्मयोगी मंच के माध्यम से, यह प्रशिक्षण आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है और पारंपरिक नियम–आधारित प्रशिक्षण से भूमिका–आधारित, योग्यता–संचालित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करता है.

प्रभाव

- कुशल और प्रभावी सिविल सेवक : यह सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करता है, जिससे उनकी भूमिकाएं अधिक प्रभावी और कुशल बनती हैं।
- आजीवन सीखने की संस्कृति : यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर सीखने और आत्म–विकास को बढ़ावा देता है, जिससे कर्मचारी नवीनतम चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
- सक्षम प्रशासन : यह तकनीकी प्रगति को अपनाकर और सरकार में विभागों के बीच की बाधाओं को खत्म करके एक मजबूत और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में मदद करता है।
- जवाबदेही और पारदर्शिता : कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मा पॉइंट और प्रमाण पत्र सिविल सेवकों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो जवाबदेही और प्रदर्शन मूल्यांकन में सुधार करता है।
- सेवा वितरण में सुधार : कुशल कर्मचारी नागरिकों को अधिक बेहतर और समय पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जो सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है।

औचित्य

- भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण : यह बदलते शासन परिवेश में सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक तकनीकी और आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि वे श्विकसित भारतश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें.
- योग्यता–संचालित क्षमता निर्माण : यह केवल नियमों का पालन करने के बजाय, व्यक्तियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान पर केंद्रित होता है, जिससे वे अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभा सकें.

– डिजिटल परिवर्तन : iGOT कर्मयोगी मंच भारत के लगभग सभी सिविल सेवकों के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, जिससे प्रशिक्षण पहले से कहीं अधिक सुलभ और एकीकृत हो गया है.

– समान अवसर : यह केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के समान अवसर प्रदान करता है, जिससे सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित होता है.

– राष्ट्र के विकास में योगदान : अंततः, यह राष्ट्र के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम सिविल सेवक प्रभावी नीति–निर्माण और सेवा वितरण सुनिश्चित करते हैं।

सरकारी संसाधन सार्वजनिक सेवाओं और मुख्य शासन संबंधी कार्यों की एक श्रृंखला के वितरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोविड–19 महामारी जैसे व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली निरंतर चुनौतियों और सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इसे संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2020 में मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हुए एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार नागरिक सेवा का निर्माण करना है।

सरकारी अधिकारी लगातार सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे सरकारी अधिकारी विभागों और क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, साइलो को तोड़ेंगे और सूचना तक पहुंच के साथ अधिकारियों को सशक्त करेंगे सरकारी नेता उच्च निष्ठा के साथ अपने जनादेश का निष्पादन करेंगे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की प्रगति का मूल्यांकन और इस प्रकार क्षमता निर्माण आयोग और विशेष उद्देश्य वाहन जैसे संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों की समग्र सफलता मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत नियम से भूमिका आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में बदलावरू

मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण भूमिका–आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से इन व्यक्तियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि नियम–आधारित, आपूर्ति–संचालित क्षमता निर्माण से भूमिका–आधारित, मांग–संचालित क्षमता निर्माण की ओर बदलाव, जहां क्षमता निर्माण को भूमिका विशिष्ट, सरकारी अधिकारियों के लिए समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारी की जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए लक्षित किया जाता है।

क्षमता विकास के लिए योग्यता संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना : एक योग्यता संचालित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण सार्वजनिक अधिकारियों के लिए अपनी विभिन्न भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (2012) के अनुरूप, मिशन कर्मयोगी ने सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण के लिए एक योग्यता ढांचा पेश किया है जो सरकारी अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति सहित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण के साथ–साथ मानव संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करेगा। योग्यताओं को दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान (ए. एस. के.) के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को किसी दिए गए कार्य में किसी कार्य या गतिविधि को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाता है।

लोकतांत्रिक बनाना और निरंतर, आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम बनाना : वर्तमान सिविल सेवा क्षमता निर्माण सेवाएँ सरकारी अधिकारियों के लिए निरंतर सीखने के वातावरण की कमी से प्रभावित हैं। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सभी सरकारी अधिकारियों को, पदानुक्रम और भौगोलिक क्षेत्रों में, अपनी भूमिकाओं के लिए आवश्यक दक्षताओं को लगातार बनाने और मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के बीच शिक्षण सामग्री तक समान पहुंच प्रदान करके, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सिविल सेवाओं के बड़े वर्गों के लिए विश्व स्तरीय क्षमता निर्माण उपलब्ध होगा।

मुख्य विशेषताएँ :

इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण–आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :

1. 'नियम आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन से 'भूमिका आधारित' प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना।
2. 'ऑफ साइट सीखने की पद्धति' को बेहतर बनाते हुए 'ऑन साइट सीखने की पद्धति' पर बल देना।
3. शिक्षण सामग्री, संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना।
4. सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना और प्रत्येक सरकारी निकाय में चिन्हित FRAC के लिये प्रासंगिक अधिगम विषय–वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना।
5. सभी सिविल सेवकों को आत्म–प्रेरित एवं अधिदेशित सीखने की प्रक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
6. प्रत्येक कर्मचारी के लिये वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एक समान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिये अपने–अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना।
7. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट–अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय–वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और साझेदारी करना।
8. क्षमता विकास, विषय–वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिये क्षेत्रों की पहचान संबंधी विभिन्न–पक्षों के संबंध में आईगॉट–कर्मयोगी द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों का विश्लेषण करना।

आईगॉट– कर्मयोगी प्लेटफॉर्म :

यह भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। इस प्लेटफॉर्म का विषय–वस्तु (कंटेंट) के संदर्भ में एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाज़ार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है जहाँ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई–लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता विकास के अलावा, सेवा मामलों जैसे कि परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टीकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।

अर्चना सिंह
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

हिन्दी : मेरी मातृभाषा

जब भी मुझको जनम मिले, बस इतना सा जिज्ञासु हूँ ;
जननी भारत माता हो, मैं एक भारत वासी हूँ।
धन–धान्य छत्र चाहे नहीं मिले, केवल इतनी सी आशा हो ;
हो संस्कार इस मिट्टी के, और मेरी, हिंदी भाषा हो।।

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर में पूजा और अज़ान हो;
हर दिल में हँसता मुस्कुराता, मेरा हिन्दुस्तान हो।
हिंदी भाषा से भारत की, एक अलग पहचान हो;
विनती करें पूरे भारत की, हिंदी ही आम ज़ुबान हो।।

माँ के मस्तक की बिंदी है, सब हिंदी का सम्मान करें ;
हिंदी भारत की भाषा है, अपनी भाषा पर मान करें।
निज भाषा पर गर्वित होकर, भाषा का व्यापक ज्ञान करें ;
हर भाषा का सम्मान करें, पर, हिंदी पर अभिमान करें।।

महेश कुमार सैनी
नेशनल इंश्योरेंस
जयपुर क्षेत्रीय लेखा हब

रिक्शा वाला

शहर की भीड़, गाड़ियां तेज़
हॉर्न की आवाज़, धुएं का जाल।
बीच सड़क पर चलता है वो,
रिक्शा खींचता, झुकता हर हाल।

पसीने की बूंदें माथे पर,
नंगे पांव कांपता जमीन पर।
पर हिम्मत उसकी कभी ना टूटे,
जीवन की गाड़ी आगे ही खींचे।

दो सवारियों की हंसी चमके,
पर उसका चेहरा थकान में दमके।
सपनों से भारी उसका सफर,
फिर भी है चलता, वो बिन थकन।

मेहनत उसकी है सच की पहचान
रिक्शा वाला है शहर की जान।

रिंकी सेहरा,
सहायक प्रबंधक, सिडबी
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र
शाखा कार्यालय

जी करता है

सब कुछ खो जाने को जी करता है ।
बचपन को फिर से पा जाने को जी करता है ।
माँ के आँचल में सिमट जाने को जी करता है ।

थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते
इक पल के लिए ठहर जाने को जी करता है
कई रातों को सोया हूँ फिर भी एक बार सो जाने को जी करता है।

कितने सपने देखे
कुछ ने मंजिल पाई
टूटे हुए सपनों को फिर से झोली में भरने को जी करता है।

कितने खिलौनों से खेला मैं
फिर भी रह गया अकेला मैं
आज फिर उन खिलौनों को पाने को जी करता है।

पूरा दिन गुज़र जाता है कई शोरों को सुनते – सुनते
फिर से जीवन के सन्नाटे को महसूस करने को जी करता है।

माँ की लॉरियों का संगीत
मेरे कानों मे जब भी रस घोलता है
जाने क्यों हर संगीत को आग लगाने को जी करता है।

दूर हो गया हूँ माँ के साये से
मेरी हठ और उसका हँस कर मना लेना
उसी प्यार को वापस पाने को जी करता है
नहीं रहेगी वो मेरे साथ
फिर भी ज़िंदगी उसके चरणों में अर्पित करने को जी करता है।

पता नहीं जिंदगी की दौड़ में किस मंजिल को पाऊँगा
फिर भी हर रास्ता उसकी ओर मोड़ देने को जी करता है
जिंदगी के सफर में वो छोड़ जाएगी किसी के सहारे
उस हमसफर से उसी प्यार को वापस पाने को जी करता है।

मर जाऊंगा एक दिन भूल जाएगी दुनिया
जाने क्यो वापस तेरी गोद में आने को जी करता है
नहीं चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए ऐश्वर्य
ऐ दुनिया तुझे होगी इनकी चाहत
मुझे माँ के अंचल में ज़िंदगी गुजरने को जी करता है।

कुँवर पाल सिंह
उप प्रबन्धक
दि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
जयपुर

भारतीय रिज़र्व बैंक की गतिविधियां

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर द्वारा हिंदी दिवस समारोह–2025 और व्याख्यान का आयोजन

भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में दिनांक 01 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 01 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने जयपुर कार्यालय के स्टाफ–सदस्यों को संबोधित करते हुए पखवाड़े का शुभारंभ किया। पखवाड़े के दौरान राजभाषा कक्ष की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया। दिनांक 12 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस समारोह और एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध लेखक श्री दिव्य प्रकाश दुबे और क्षेत्रीय निदेशक महोदय श्री नवीन नंबियार उपस्थित थे। क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्माहनित भी किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के जयपुर कार्यालय को राजभाषा शील्ड पुरस्कार

दिनांक 22 सितंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा जयपुर कार्यालय को वर्ष 2024–25 के लिए राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही, गवर्नर महोदय द्वारा जयपुर कार्यालय की गृह पत्रिका "झरोखा" को वर्ष 2024–25 के लिए 'क क्षेत्र' में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा राजभाषा संदर्शिका पुस्तिका का विमोचन

दिनांक 08 दिसंबर, 2025 को राजभाषा संदर्शिका पुस्तिका का विमोचन कार्यपालक भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा किया गया। जयपुर कार्यालय की इस पुस्तिका में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, अधिनियम, संकल्प, नियम, वार्षिक कार्यक्रम, हिंदी शिक्षण योजना, जांच बिंदु, देवनागरी मानकीकरण, हिंदी में टिप्पण और ई–मेल/नोट में प्रयुक्त वाक्यों की द्विभाषी सूची जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया हैं जो सभी स्टाफ–सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

पंजाब नैशनल बैंक की गतिविधियां

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा राजभाषा समारोह का आयोजन

दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को पंजाब नैशनल बैंक के अंचल कार्यालय, जयपुर में श्री राजेश भौमिक, महाप्रबंधक की अध्यक्षता में राजभाषा समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंचल द्वारा मनाए गए हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में अंचल के विभिन्न मंडलों को भी पुरस्कृत किया गया। आयोजन के दौरान कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें श्री अमित तिवारी 'आज़ाद', श्री नवीन कानूनगो, सुश्री नम्रता गुप्ता ने कविता पाठ कर समां बांध दिया। श्री शैलेश कुमार के हिन्दी गीतों की सम्मोहक आवाज ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अजय सक्सैना, वरिष्ठ प्रबंधक–राजभाषा व डॉ. ममता मीना, प्रबन्धक–राजभाषा, जयपुर–अजमेर मण्डल द्वारा किया गया।

नाबार्ड की गतिविधियां

नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन

बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में राजभाषा अनुभाग, नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 17.12.2025 को विनय भारती बाल मंदिर में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा 8,9,10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई।

भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन

दिनांक 15 सितंबर, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय स्तर पर 'चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया।

दिनांक 16 सितंबर, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, जयपुर द्वारा 'मंडल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीता शर्मा, रश्मि गोस्वामी, एवं लाजवंती गुरबानी भी उपस्थित रहीं।

दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मण्डल स्तर पर टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर द्वारा मंडल कार्यालय स्तर पर 'वर्ग पहेली प्रतियोगिता' का आयोजन।

दिनांक 24 सितंबर, 2025 को मंडल कार्यालय स्तर पर मुहावरे एवं लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सूक्तियां–दोहे, अंग्रेज़ी कहावतों के हिंदी पर्याय एवं शब्दों से हिंदी गाने बूझें जैसे विषयों पर आधारित मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक 'प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता' का आयोजन इस अवसर पर प्रबंधक कार्मिक श्री सुदीप बैनर्जी व श्री पवन कुमार, प्रबंधक सम्पदा श्री वी.एन.विजय, प्रबंधक कार्यालय सेवा श्रीमती कविता गंगल भी उपस्थित रहे।

दिनांक 29 सितंबर, 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम–प्रथम कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के समापन दिवस के अवसर पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

यूको बैंक की गतिविधियां

अंचल कार्यालय, यूको बैंक द्वारा यूको राजभाषा सम्मान समारोह आयोजित

अंचल कार्यालय, यूको बैंक द्वारा 17 दिसंबर, 2025 को 'यूको राजभाषा सम्मान' के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में एम.ए. (हिंदी) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले दो छात्रों को अंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार ने 5000/– (प्रत्येक छात्र) से सम्मानित किया।

नराकास, जयपुर के तत्वावधान में यूको बैंक द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाकसू में प्रतियोगिताएं आयोजित

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के तत्वावधान में यूको बैंक द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2025 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाकसू में चित्रकला, भाषण तथा कविता प्रतियोगिता का आयोजन श्री मुकेश कुमार राजभाषा अधिकारी अंचल कार्यालय यूको बैंक जयपुर एवं श्री नितिन कुमार शाखा प्रबंधक चाकसू शाखा, प्रधानाचार्य महोदया रजनी शर्मा एवं उप प्रधानाचार्य मंजू देवी की उपस्थिति में किया गया।

अंचल कार्यालय, यूको बैंक में हिंदी पखवाड़ा आयोजित

अंचल कार्यालय, यूको बैंक द्वारा हिंदी माह के अवसर 25 सितंबर, 2025 पर आशुभाषण प्रतियोगिता तथा मूक पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजयी प्रतिभागियों को अंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार ने पुरस्कृत किया गया।

बढ़ता शहरीकरण और निम्न वर्ग की जनसंख्या के लिए आवास की समस्या

शहरों में निम्न वर्ग की जनसंख्या के लिए आवास की समस्या का प्रारंभ :

विकास में शहरीकरण की अवधारणा

वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गाँवों के सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंधमूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिये। मानव जीवन को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे वायु–जल प्रदूषण, कानून और व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा, आवागमन के साधनों, पीने के साफ़ पानी , स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता विकसित समाज के लिए अत्यन्त जरूरी है। यह कहा जा सकता है कि विकास और शहरों में गाँव से पलायित निम्न वर्ग की एक बड़ी जनसँख्या को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी और कपडा तो सुलभ है परन्तु मकान/आवास की समस्या का एक–दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है।

कुछ समय पूर्व स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। नवीन भारत की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढाँचों में सुधार के लिये शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

विकास का प्रतीक शहरीकरण और निम्न वर्ग का शहरों की ओर पलायन

शहरी क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाएँ अधिक होती हैं, इसलिये वहाँ ज्यादा लोग रोज़गार में लगे होते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वे अधिक धन कमाते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं।आँकड़ों के अनुसार, 2001 तक भारत की आबादी का 27.81% हिस्सा शहरों में रहता था। 2011 तक यह 31.16% और 2018 में 33.6% हो गया। 2001 की जनगणना में शहर–कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो 2011 में बढ़ कर 7936 हो गई। आज हर तीन भारतीयों में से एक शहरों और कस्बों में रहने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।

तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढोतरी को आवास संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी में तीन गुना वृद्धि हो चुकी होगी और यह कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। इस बढ़ती हुई शहरी आबादी को देखते हुए आवास, पानी, पर्यावरण, हिंसा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अस्वच्छ स्थानों पर आवासित होने के कारण, अस्वास्थ्यकर आहार, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएँ और खतरे भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं।

संपत्ति का असंतुलन

शहरों में संपत्ति संबंधी और आर्थिक असमानता अधिक पाई जाती है, या कहें कि प्रत्येक प्रकार की असमानता का केंद्र शहर ही हैं। भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.4% हिस्सा है। इनमें से भी सिर्फ एक प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 51.53% हिस्सा है। भारत की 60% आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8% संपत्ति है। देश के शीर्ष नौ धनवानों की संपत्ति 50% गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है।

शहरों में बढ़ती स्लम बस्तियाँ

देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियाँ बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।हमारे देश का लगभग हर शहर की झुग्गी बस्तियां सार्वजनिक सुविधाओं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित

है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण ने शहरों में असमानताओं को जन्म दिया है।शहरों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल–जमाव से होने वाली परेशानियाँ, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त–व्यस्त व असमान रूप शहरी जीवन को इतना अधिक समस्यामूलक बना देता है कि कई शहरों में रहने की कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है।अपराध की दृष्टि से भी शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं...कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है। नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गाँव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता बनकर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गाँव अपने अस्तित्व के लिये इन शहरों से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने लगी है।

असंतुलित शहरी विकास

आज देश के सम्मुख शहरीकरण का प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। शहरों की चकाचौंध आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये हमेशा से ही आकर्षण का विषय रही है और वे प्रायः इस आकर्षण के वशीभूत होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जहाँ पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहाँ पहुंच कर वे भी आवास, जलापूर्ति, जलमल निकासी, स्थानीय परिवहन और रोज़गार के अवसरों जैसी पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं । शहरी गरीब अनेक जटिल रोगों सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारों की अधिकांश बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है । अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियाँ शहरों का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल और कचरे के निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं मिल पातीं।

शहरीकरण को लेकर सरकार की प्राथमिकता

शहरी क्षेत्रों का सतत, संतुलित् एवं समेकित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता एवं शहरी विकास का एक केंद्रीय विषय है। जिस तरीके से देश में 'शहरीकरण' की प्रक्रिया का प्रबंधन होगा, उसी से यह निर्धारित होगा कि किस सीमा तक शहरी अवस्थांतर का लाभ उठाया जा सकता हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन में शहरों के उभरने से भारत अपनी विकास यात्रा के एक अहम पड़ाव पर है, जहाँ शहरों/कस्बों के विकसित होने, संपन्न होने तथा निवेश एवं उत्पादकता का व्यावसायिक केंद्र बनने के लिये पर्याप्त अवसरों का सृजन अवश्य किया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति को कम करने के लिये स्मार्ट सिटी मिशन जैसे अभियानों को पर्यावरण, सतत एवं अवसंरचना विकास के लिये अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयासों, उत्सर्जन में कमी एवं आपदा के प्रति शहरों का लचीलापन बढ़ाने के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी सब–मिशन भी शुरू किया गया है। इसके अलावा शहरों में रहने की उपयुक्तता के मापन की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजना में सभी 79 संकेतक विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन से लेकर पानी के दोबारा इस्तेमाल, प्रदूषण आदि को शामिल किया गया है।

मानसून आते ही हर साल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश होती है। और बारिश शुरू हुई नहीं कि थोड़ी ही देर में शहर के कई इलाकों में जलजमाव का नज़ारा दिखने लगता है। कहीं कमर तक लगे पानी में सैकड़ों गाड़ियां फंस जाती हैं, तो कहीं सड़कों पर जाम लग जाता है। लोगों के घर के सामान पानी में बह रहे होते हैं। हर साल बड़ी तादाद में लोग बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं और करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त–व्यस्त हो जाता है।

इस बार भी मुंबई में जोरदार बारिश हुई है जिसने पिछले 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर ताज़ुजुब की बात है कि हम हर साल इस समस्या से जूझते हैं लेकिन आज तक इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ़ पाए। ऐसे में हमारी शहरी प्लानिंग की व्यवस्था पर सवाल उठाना लाज़मी है।

शहरी क्षेत्र का उद्भव और आवास की समस्या का आगाज

भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक़ अगर किसी इन्सानी बस्ती की आबादी में 5000 या उससे ज्यादा लोग हों, इस आबादी के कम से कम 75 फीसद लोग गैर–कृषि व्यवसाय में लगे हों,वहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से ज्यादा हो,साथ ही यहाँ कुछ और विशेषताएँ मसलन उद्योग, बड़ी आवासी बस्तियां, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्था हो तो इस बस्ती को नगर की परिभाषा के तहत माना जाता है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार मसलन क्षेत्रफल,

जनसंख्या जैसे कारकों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक़, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और वहाँ काम करना भी 'शहरीकरण' ही है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब तक विश्व की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।

संयुक्त राष्ट्र के ही एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2050 के बीच बढ़ने वाली आबादी में पैंतीस फीसद हिस्सेदारी भारत, चीन और नाइजीरिया की होगी। अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में 41.6 करोड़, चीन में 25.5 करोड़ और नाइजीरिया में 18.9 करोड़ शहरी आबादी बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक स्टडी के मुताबिक़ साल 2019 और 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले सभी शीर्ष 10 शहर भारत में हैं।साल 2011 की जनगणना के मुताबिक़, हमारे देश की जनसंख्या का 31.16 फीसद हिस्सा शहरों में रहता है लेकिन अगर सेटेलाइट से मिली तस्वीरों को आधार बनाया जाए तो दो तिहाई यानी तिरसठ फीसद भारत शहरी नज़र आएगा। भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी–झोपड़ी में रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार 2.9% शहरी घर टूटे–फूटे हालत में हैं। शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 70% योगदान करते हैं लेकिन भूमि आधार पर मात्र 4% का हक़ रखते हैं।

शहरीकरण के कई कारण रहे हैं लेकिन व्यापक आधार पर इसे तीन वर्गों में बांटा जा सकता है – (i) कुछ लोग शहरों की तरफ आकर्षित होकर यहाँ रहने के लिए आते हैं (ii) कुछ लोग मज़बूरीवश आते हैं (iii) साथी ही, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किसी विशेष कारण के चलते शहरों की तरफ आना पड़ता है। बहरहाल अगर कुछ खास कारणों पर ग़ौर करें तो इनमें निम्नलिखित वजहों को शुमार किया जा सकता है–

- द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप सरकारी सेवाओं में विस्तार
- भारत–विभाजन के दौरान लोगों का पलायन
- औद्योगिक क्रांति
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना – जिसमें भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण को लक्ष्य बनाया गया था।

बेहतर आर्थिक अवसरों के लालच और रोज़गार की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन आदि। साल 1990 के बाद प्राइवेट सेक्टर का विकासग्रामीण क्षेत्रों में जोत की ज़मीन का कम होना, परिवार का बड़ा आकार और जाति प्रथा जैसे दूसरे ऐसे कारक है जिसके चलते लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कृषि में होने वाले नुकसान की वज़ह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक़ खेती पर निर्भर लोगों में से 40 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको अगर विकल्प मिले तो वे तुरंत खेती छोड़ देंगे। क्योंकि खेती करने में धन की लागत बढ़ती जा रही है।

उपरलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि जिस रफ़्तार से शहरों का जन्म हुआ उसी रफ़्तार से आवासों का निर्माण नहीं हुआ। विस्तार हुआ केवल निम्न वर्गीय जनता के लिए झुग्गी बस्तियों का। सरकारों का ध्यान इस महती समस्या पर बहुत देरी से गया तब तक विभिन्न शहरों में के निचले और दलदली इलाके, रेलवे लाइन के अगल बगल और गंदे नालों के पास करोड़ों लोग रहने लगे। आज की स्थिति में सरकार द्वारा निम्न वर्ग के लोगों के लिए शहरों में समुचित आवास की व्यवस्था करना एक चुनौती बना हुआ है।

भारत में शहरीकरण की प्रकृति

विश्व बैंक की साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत का शहरीकरण Hidden and Messy यानी "अघोषित और अस्तव्यस्त" है। भारत में शहरी फैलाव, देश की कुल आबादी का 55.3 प्रतिशत है और आधिकारिक जनगणना के आंकड़े इसे केवल 31 फ़ीसदी ही बताते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि अकेले दक्षिण एशिया में क़रीब 130 मिलियन लोग अस्थायी बस्तियों जैसे कि मलिन बस्तियों और अव्यवस्थित रूप से फैले क्षेत्रों में निवास करते हैं। अघोषित यानी छिपा हुआ शहरीकरण भारत की आबादी के बड़े हिस्से में

देखा जाता है जिसमें शहरी विशेषताएं तो हैं लेकिन ये आधिकारिक रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंडो को पूरा नहीं करते हैं। बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा तेज़ी से हुई है वहीं इसके मुक़ाबले छोटे शहरों में शहरीकरण की दर या तो स्थिर रही है या फिर कम हुई है। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़ूयादा है वहां पर शहरीकरण की दर भी ज्यादा है वहीं इसकी तुलना में जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहां पर शहरीकरण की दर भी कम है।

शहरीकरण का महत्व

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक़, दुनिया की 54 फ़ीसदी से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80 प्रतिशत का योगदान करती है और दो–तिहाई वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। साथ ही 70 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है।शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।उत्पादकता को बढ़ाता है और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।शहरीकरण के चलते तमाम अलग–अलग संस्कृतियों और परंपराओं को एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर मिलता है।प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों रहन–सहन का स्तर बेहतर होता है।शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति–प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अब ध्वस्त हो रही हैं।

शहरीकरण में उपयुक आवास की अनुपलब्धता और भारतीय परिवार पर असर

शहरों में उपयुक आवास की अनुपलब्धता का असर पारिवारिक संरचना और व्यवस्था पर देखने को मिलता है। परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्ते, दो परिवारों के बीच का रिश्ता और परिवार के काम – इन सब पर असर पड़ा है। शहर में जॉइंट परिवार के बजाय न्यूक्लियर परिवारों का चलन बढ़ रहा है। रिश्तेदारी केवल दो या तीन पीढ़ियों तक सीमित हो रही है।

इसके अलावा, पति के वर्चस्व वाला परिवार अब समानतावादी परिवार में बदल रहा है यानी पत्नी को भी निर्णय लेने की आज़ादी मिलने लगी है। माता–पिता अब बच्चों पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं और बच्चे अब आँख बंद करके अपने माता–पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। शहरी संयुक्त परिवारों में, अब घर के बड़े–बुजुर्ग भी किसी महत्वपूर्ण बात में अपने से छोटे के साथ राय मशविरा करते हैं।

शहरीकरण से जुड़ी मुख्य समस्याओं में केवल आवास की समस्या के साथ भीड़ और व्यक्तिवाद की भावना,पानी की आपूर्ति और जल निकासी का बेहतर न होना,शहरी बाढ़,परिवहन और यातायात की समस्या,बिजली की कमी, प्रदूषण, अपराध और बाल अपराध, भीख, शराब और ड्रग्स की समस्या और भ्रष्टाचार भी हैं।

शहरी विकास की तीन प्रमुख समस्याएं जिनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवास की समस्या भी संलग्न है। शहरी विकास में कई समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ जनसंख्या के विस्तार के कारण हैं और कुछ शहरों के भौतिक विस्तार के कारण हैं। शहरी विकास की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1. रोजगार :

ग्रामीण–शहरी प्रवास सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन यह हमेशा की तरह एक बड़ी समस्या नहीं रही है। वास्तव में, जहां बहाव धीरे–धीरे होता है और इसमें केवल छोटी संख्याएँ शामिल होती हैं, जिन्हें आमतौर पर समाहित किया जा सकता है, और यह लगभग हमेशा अतीत में ऐसा होता था जब जनसंख्या संख्या छोटी थी।कभी–कभी यह हाथ से निकल जाता था, जैसे कि ब्रिटेन और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान जब हजारों लोग कस्बों में आते थे, तो आंशिक रूप से कृषि परिवर्तनों के परिणामस्वरूप। कस्बों में भीड़भाड़ के कारण आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मानकों में गिरावट आई। हालांकि, प्रवासियों के लिए कुछ उम्मीद थी क्योंकि बढ़ते उद्योगों ने रोजगार प्रदान किया, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारियों को अक्सर बुरी तरह से भुगतान किया गया था।

आजकल शहरीकरण की समस्याएं अधिक हैं, विशेष रूप से अविकसित देशों में, दुनिया भर में आबादी का तेजी से विस्तार हुआ है और बढ़ती दर पर विस्तार करना जारी है, ताकि शहरीकरण में भी कहीं अधिक संख्या में शामिल हों। इसके अलावा, कई मामलों में, कस्बों में घूमने वाले लोग बेरोजगार हैं।

आवास और स्वास्थ्य के मानक इसलिए कम हैं और यह अविकसित देशों में सार्वजनिक सेवा विभागों को एक कार्य देता है, जो अक्सर हल करने के लिए उनकी शक्तियों से परे होता है। उन्नत देशों में शहरी विकास कम समस्याएं पैदा करता है, कस्बों और शहरों में बड़ी जनसंख्या सांद्रता के कारण नए औद्योगिक विकास आकर्षित होते हैं, और परिणामस्वरूप प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

2. सामाजिक सेवाओं का प्रावधान :

कोलकाता, लागोस, मनीला या रियो डी जनेरियो जैसे शहरों में प्रवासियों की गरीबी सामाजिक सेवाओं जैसे आवास, पानी, स्वच्छता और सीवेज निपटान की समस्याओं को बढ़ाती है। विकास की गति ऐसी है कि कुछ शहरों में सुधार की योजना केवल समस्या की सतह पर खरोंच है। एक क्षेत्र से साफ किए गए स्क्वाटर्स दूसरे में बस सकते हैं, जब तक कि उनके लिए आवास नहीं मिल सकता है। आधुनिक आवास विकास द्वारा भीड़भाड़ वाले कस्बों में आबादी के घनत्व का मिलान करना बहुत मुश्किल है, ताकि झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को शहर के आवास अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए नए घरों से अनिवार्य रूप से बाहर निकलना पड़े।

यह कभी–कभी उन्नत देशों के शहरों में भी सच होता है जहां उन्नीसवीं शताब्दी के पुराने टेनेमेंट और श्रमिकों के आवास, ज्यादातर शहरों के भीड़भाड़ वाले दिल में, अक्सर झुग्गी हालत में होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भूमि की कमी है कि नए घर तब तक नहीं बनाए जा सकते जब तक कि मलिन बस्तियों को साफ नहीं किया जाता है। इस मामले में समस्या यह है कि नए घर बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को घर देना है। इस प्रकार लगभग हर जगह रहने की स्थिति में सुधार करने में प्रगति की दर बहुत धीमी है।

3. शहरी फैलाव :

शहर की विकास की प्रमुख समस्याओं में से एक तेजी से बढ़ते शहरों का क्षेत्र विस्तार है। दुनिया के लगभग सभी देशों में आसपास की कृषि भूमि की कीमत पर शहर बढ़ रहे हैं। विकसित और अविकसित दोनों देशों में, शहर के निवासियों के अमीर वर्ग लगातार शहरों के भीड़ भरे केंद्रों से अधिक सुखद उपनगरों की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे बड़े घर बना सकते हैं।

कई देशों में, कस्बों के बाहरी इलाकों में स्क्वैटरों का कब्जा है, जो अप्रयुक्त भूमि पर मेकशिफ्ट शक्स का निर्माण करते हैं, हालांकि उनके पास भूमि का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किसी भी मामले में शहर के विकास को प्रतिबंधित करने की कठिनाई बहुत अधिक है, और अधिकांश शहर उपनगरों के विस्तृत छल्ले से घिरे हुए हैं।

ऐतिहासिक रूप से, उपनगर सबसे पहले प्रमुख सड़कों के किनारे उग आए हैं, जो कस्बों में रिबन बस्तियों के रूप में जाती हैं। इस तरह की साइटें सबसे पहले उनकी पहुंच के कारण विकसित की जाती हैं, लेकिन जल्द ही उपनगरीय घरों की मांग के कारण रिबन बस्तियों के बीच की भूमि को खरीदा जा सकता है, नई सड़कों के निर्माण से बनाया और बनाया जा सकता है। इस तरह के विकास को इन्फिल के रूप में जाना जाता है। इसी समय, बड़े शहरों में आने वाले छोटे शहरों और गांवों को आवासीय उपयोग के लिए भी विकसित किया जाता है। इस तरह, शहर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में, कई पड़ोसी शहरों के उपनगर इतने करीब हो सकते हैं कि एक निरंतर सतत शहरी विकास का निर्माण हो सकता है जिसे एक अभिसरण कहा जाता है। यूरोप और अमेरिका में अभिसमय के कई उदाहरण मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी सीबोर्ड के लगभग निरंतर विकास में कई बड़े शहर और उनके संबंधित उपनगरीय क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें मेगालोपोलिस कहा जाता है।

बहुत से लोग यह अनुमान लगाते हैं कि दक्षिण–पूर्व इंग्लैंड, जहाँ शहर तेजी से बढ़ते ग्रामीण इलाकों की कीमत पर बढ़ रहे हैं, एक दिन लगभग एक ही शहरी क्षेत्र होगा। अन्य अनुमान अंग्रेजी मिडलैंड्स में पाए जाते हैं, जहां बर्मिंघम, स्मेथविक, वेस्ट ब्रोमविच, वॉल्सल और वॉल्वरहैम्प्टन के साथ–साथ कई छोटे शहरों के कस्बे, ब्लॉक देश नामक औद्योगिक और खनन विकास के एक व्यापक क्षेत्र में लगभग विलय हो गए हैं। जापान में तीन सबसे बड़े शहर, टोक्यो, नागोया और ओसाका, विशाल सम्मेलनों के केंद्र हैं और एक शहरी गलियारे के आवास का निर्माण करते हैं, जितने लोग पूरे इंग्लैंड में करते हैं और एक मेगालोपोलिस की तुलना में कहीं अधिक है।

ब्रिटेन और कई अन्य देशों में, एक ग्रीन बेल्ट नीति शहरी फैलाव के तेजी से विस्तार को प्रतिबंधित करने के प्रयास में मुख्य शहरों के आसपास के क्षेत्र में नई इमारतों को प्रतिबंधित करती है। अविकसित देशों में शहरी विकास की समस्याएं अक्सर अलग होती हैं। मुख्य समस्या स्क्वैटर क्षेत्रों की स्थितियों में सुधार करना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है जब शहर की अधिकांश आबादी दरों और करों के लिए योगदान नहीं करती है जो इस तरह के विकास को वित्त प्रदान करते हैं। साथ ही धनी वर्गों की उपनगरीय घटनाओं में फैलाव को सीमित करने की समस्या को भी दूर करना होगा।

उन्नत देशों की तरह, सट्टा बिल्डर्स उच्च श्रेणी के आवास बनाने के लिए अधिक इच्छुक हैं, जिससे वे श्रमिक वर्ग परिवारों के लिए आवश्यक आवास बनाने की तुलना में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार आवास समस्या का खामियाजा उन सरकारों पर पड़ता है जो पहले से ही अपने देशों के समग्र विकास में बड़ी वित्तीय समस्या का सामना करती हैं। कई अविकसित

देशों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के निचले मानकों द्वारा अतिरिक्त उपभेदों को लगाया जाता है और तेजी से बढ़ती आबादी के लिए अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

शहरीकरण के कारण पैदा हुई विभिन्न अंतर्बद्ध समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपाय

- स्मार्ट सिटी मिशन
- कायाकल्प और शहरी रूपान्तरण के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)
- सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान स्कीम
- स्वच्छ भारत अभियान
- हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)
- राजीव आवास योजना
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
- क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड

आवास की समस्या के निदान के उपाय

भारत में शहरी अनुशासन ख़राब होने और वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, पैसों की कमी, जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव, विभिन्न एजेंसियों (जैसे पानी, परिवहन आदि) के बीच बेहतर समन्वय का न होना, समुचित शहरी विकास नीति का अभावअनुचित शहरी नियोजन शहरों में आवास की समस्या को और बढ़ा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ–साथ पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण (Diversification) करने की ज़रूरत है। इस मामले में, मनरेगा ने गावों से शहरों की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभाई है जिससे शहरों पर जनसँख्या का बोझ कम होगा। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास पर जोर देना होगा।भारत को गाँवों का देश कहा जाता है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है।देश के आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिये यह कल्पना करना बेमानी होगा कि गाँव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। थोड़ी सी सुविधाएँ प्रदान कर देने मात्र से गाँवों का विकास होना बहुत मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ अगर गाँवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।ग्रामीण विकास के ज़रिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिये आवास और बुनियादी सुविधाएँ आर्थिक विकास के मुख्य वाहक हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एजेंडा समावेशी विकास पर आधारित है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुँचे। ग्रामीण संकट का मूल कारण वहाँ रहने वालों की आय का कम होना है। इसके लिये सरकार ने रोज़गार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता से संबंधित कई योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की गई है।

शहरों की लोकल प्लानिंग और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए स्टैण्डर्ड व्यवस्थाओं को विकसित किया जाना चाहिए।समावेशी शहरीकरण की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शहरी गरीब और अन्य कमजोर समूहों की आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक रोज़गार और सुरक्षित वातावरण जैसी ज़रूरतें पूरी की जाएँ। पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण : शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन, ग्रीन पैचेज का विकास, आर्द्रभूमि, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, बेहतर ढांचागत सुविधाएं– आवास, पानी, सीवेज और बिजली सुनिश्चित करना बेहतर अर्बन गवर्नेंस को सुनिश्चित करना – इसके तहत राजकोषीय विकेंद्रीकरण और पर्याप्त धन की उपलब्धता, नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों का सशक्तीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही, एवं नागरिक भागीदारी जैसेक़दम उठाये जा सकते हैं।

अनुराग तिवारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
अंचल कार्यालय, जयपुर

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की गतिविधियां

सिडबी जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिंदी कार्यशाला आयोजित

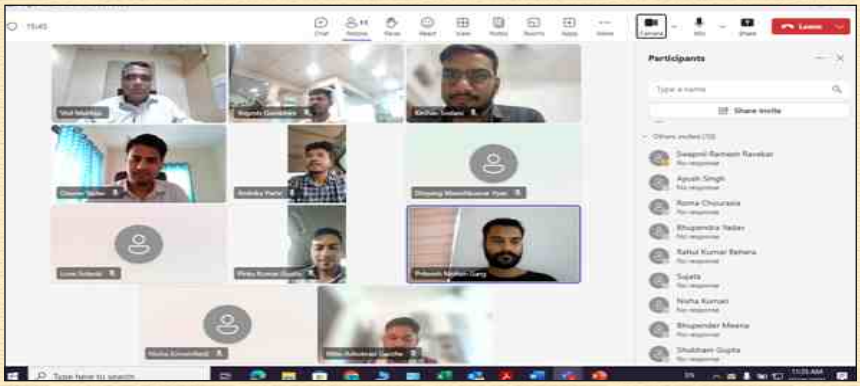

सिडबी, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2025 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राजभाषा नीति का परिचय, बैंकिंग शब्दावली तथा मानक वर्तनी विषयक सत्र रखे गए थे। इसमें 16 अधिकारियों ने सहभागिता की।

सिडबी में हिंदी पखवाड़ा आयोजित

सिडबी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर एवं शाखा कार्यालय में दिनांक 14 से 30 सितंबर, 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत कुल 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही, क्षेत्रांतर्गत अन्य 5 शाखाओं के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सितंबर माह में अधिकाधिक कामकाज हिंदी में करने हेतु 2 स्टाफ सदस्यों को रु.3100 के नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

केनरा बैंक की गतिविधियां

केनरा बैंक द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

दिनांक 20 सितंबर, 2025 को केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालय, जयपुर में संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस समारोह–2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक सुश्री गीतिका शर्मा, अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक श्री संजय कुमार क्षेत्रीय, प्रमुख, जयपुर क्षेत्र श्री एम.गांधी, मुख्य अतिथि एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. उर्मिला साध एवं अन्य कार्यपालक तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

'हिंदी में परिचर्चा–कार्यक्रम' का आयोजन

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को प्रधान कार्यालय द्वारा दिसंबर–2025 तिमाही के लिए दिए गए विषय 'सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका' पर 'हिंदी में परिचर्चा– कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विपिन श्याम बिहारी ठाकुर ने की।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गतिविधियां

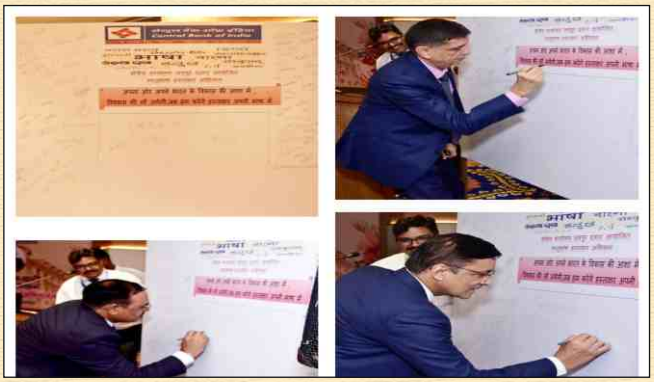

दिनांक 22 अगस्त, 2025 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा मातृभाषा में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया जिसमें बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के साथ–साथ बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही महोदय, केन्द्रीय कार्यालय से पधारे महाप्रबंधक श्री वास्ती वेंकटेंश, दिल्ली अंचल के अंचल प्रमुख श्री शीशराम तुंदवाल तथा जयपुर क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख श्री शैलेश वर्मा ने भी अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाया।

दिनांक 13 सितंबर, 2025 को सैंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हिन्दी माह का शुभारंभ किया गया जिसमें दिनांक 14.09.2025 से दिनांक 14.10.2025 तक हिन्दी माह मनाते हुए अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया गया साथ ही सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा राजभाषा प्रतिज्ञा ग्रहण किया गया।

दिनांक 18 सितंबर, 2025 को हिन्दी माह के दौरान सभी स्टाफ सदस्यों हेतु आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 को हिन्दी माह के दौरान सभी अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों हेतु हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 19 दिसंबर 2025 को बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्रीनगर में कक्षा सातवी, आठवीं, तथा नौवीं के छात्र–छात्राओं हेतु प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को राजभाषा विभाग द्वारा सभी स्टाफ सदस्यों के बच्चों हेतु चित्राकंन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक

हिंदी दिवस 2025

दिनांक 27 सितंबर, 2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा हिन्दी दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्का र बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री निधिर कांत ने प्रदान किया।

''मशीनी अनुवाद हेतु सॉफ्टवेयर'' विषय पर वेबीनार

दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के मुख्यं वक्ता निरीक्षक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय श्री दीपक कुमार रहे।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक का राजभाषा निरीक्षण

दिनांक 03 जुलाई, 2025 को वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक श्री धर्मवीर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक श्री निधिर कांत भी उपस्थित रहे।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यि वक्ता के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री ओ पी अग्रवाल आमंत्रित रहे। कार्यक्रम में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री निधिर कांत भी उपस्थित थे।

नेशनल इंश्योरेंस की गतिविधियाँ

नेशनल इंश्योरेंस, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित

नेशनल इंश्योरेंस, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमृत लाल मीणा के मार्गदर्शन में दिनांक 14 से 26 सितंबर, 2025 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्माानित किया गया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की गतिविधियाँ

दिनांक 14–15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2025 एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक आयोजित कंठस्थ 2.0 "ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं में जयपुर क्षेत्र से अनुवादक श्रेणी में सुश्री नारायणी देवी, प्रबंधक (राजभाषा) को श्रीमती अंशुली आर्य, सचिव, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, डॉ. देबदत्त चांद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक के करकमलों से तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को बैंक नराकास, जयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिन्दी सेमिनार एवं वार्षिक राजभाषा समारोह में वर्ष 2024 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार बैंक के प्रमुख–राजभाषा और संसदीय समिति श्री संजय सिंह, प्रमुख– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान श्री राजकुमार मीना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. की उप महाप्रबंधक श्रीमती रचना गर्ग एवं ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के उप महाप्रबंधक श्री संजय जैन के कर कमलों से जयपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख श्री देबाशीष बक्सी ने प्राप्त किया।

आईडीबीआई बैंक की गतिविधियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 1 नवंबर 2025 को आईडीबीआई बैंक की भरतपुर शाखा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोशीबा, भरतपुर में एक सभा का आयोजन किया गयाद्य शाखा प्रबन्धक श्री अभिषेक जैसवाल ने विद्यार्थियों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी तथा इससे बचाव के उपाय भी बताए। सभा के दौरान विद्यार्थियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में हिंदी दिवस 2025 का आयोजन

हिंदी दिवस, 2025 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2025 को जयपुर क्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फार्म के माध्यम से "हिंदी शब्द ज्ञान" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री अमित कुमार तिवारी सहित 174 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

हिंदी दिवस, 2025 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26.09.2025 को जयपुर क्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फार्म के माध्यम से "बूझो तो जानें हिन्दी पहेली" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय प्रमुख श्री देबाशीष बक्शी एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री अमित कुमार तिवारी सहित 209 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

मेरी पसंदीदा पुस्तक : गोदान

मेरी पसंदीदा पुस्तक "गोदान" है जो हिन्दी साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक माना जाता है और जो भारतीय सामाजिक यथार्थ, ग्रामीण जीवन की पीड़ा, आर्थिक विषमता, स्त्री–पुरुष संबंधों, जाति व्यवस्था, पूंजीवाद, सामाजिक–राजनीतिक विसंगतियों तथा नैतिक द्वंद्वों को समेटने वाला एक बहुआयामी ग्रंथ है जो न केवल एक किसान की कथा कहता है बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को शब्दों में बांधता है; प्रेमचंद ने इसे 1936 में अपने जीवन के अंतिम वर्ष में पूरा किया था और इस उपन्यास को उन्होंने भारतीय किसान की 'गोदान' की पौराणिक परंपरा से जोड़ा, जो एक प्रतीक है– उस अंतिम बलिदान, पुण्य, या आत्मिक तृप्ति का जो मृत्यु के समय किसी गरीब के लिए भी सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मानी जाती है लेकिन उपन्यास में नायक होरी को यह साधारण–सी धार्मिक आकांक्षा पूरी करने का अवसर भी नहीं मिलता जिससे यह स्पष्ट होता है कि शोषण, अन्याय, और सामाजिक–सांस्कृतिक जकड़न ने किस प्रकार एक मेहनतकश किसान को जीवन भर पीसकर मार डाला है और अंततः वह उस गाय के दान की आकांक्षा तक नहीं पहुंच पाता जो प्रतीक बन जाती है।

भारतीय समाज में गरीब की अधूरी इच्छाओं, असमानताओं और विडंबनाओं को लेकर गोदान की केंद्रीय प्रतीकात्मकता इस उपन्यास को एक अत्यंत मार्मिक, यथार्थपरक और समय से परे जाकर प्रासंगिक बना देती है क्योंकि इसमें एक किसान की कथा, उस समय की समाज–व्यवस्था, जब भारत आज़ादी के करीब था का वर्णन है। ग्रामीण भारत आज़ादी से कोसों दूर–शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और न्याय की मूलभूत सुविधाओं से वंचित; इस उपन्यास के केंद्र में है होरी, जो परंपरागत भारतीय किसान है–ईमानदार, मेहनती, धार्मिक, अपने संस्कारों के प्रति निष्ठावान, परिवार के प्रति समर्पित और समाज के दबावों में पिसता हुआ ऐसा व्यक्ति, जो अपने कर्म और धर्म के बीच की खाई में गिरकर बार–बार उठता है, गिरता है, लड़ता हैपर फिर भी समाज द्वारा नियत की गई सीमाओं को पार नहीं करता; उसके चरित्र में वह दृढ़ता है जो सच्चे भारतीय किसान में होती है – जो बारिश के लिए ईश्वर की ओर देखता है जो ज़मींदार के सामने झुक जाता है, जो बेटा गलत करता है तो भी उससे मुँह नहीं मोड़ता और जो अंतिम क्षणों में भी अपने विश्वासों को नहीं छोड़ता; प्रेमचंद ने होरी को नायक के रूप में प्रस्तुत करके एक सामान्य किसान को असाधारण बना दिया है – उसकी पीड़ा, उसकी चाह, उसकी विवशता, उसका धर्म, और उसका अंत – सब कुछ इतना सजीव और यथार्थ है कि पाठक स्वयं को होरी के साथ चलते हुए अनुभव करता है; लेकिन केवल होरी ही नहीं, धनिया का पात्र भी उतना ही सशक्त और केंद्रीय है– एक ग्रामीण स्त्री जो अपने पति की मूर्खताओं और समाज की रूढ़ियों के बीच स्वयं को परिवार की रीढ़ बना लेती है जो निर्णय लेने में निर्भीक है बहू को अपनाने में समाज के भय को दरकिनार करती है।

पंचायत में पति की मर्यादा की रक्षा करती है और जब गोबर पिता की अवज्ञा कर जाता है तब भी उसे माफ़ करके घर लाती है जो यह दिखाता है कि भारतीय ग्रामीण समाज में स्त्री केवल घर तक सीमित नहीं बल्कि वह नैतिक और सामाजिक मूल्यों की संरक्षक भी है; गोबर, होरी का बेटा, एक ऐसा पात्र है जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के टकराव का प्रतीक है – वह विद्रोह करता है, भागता है, नौकरी करता है, शहर की ओर उन्मुख होता है लेकिन अंततः अपने परिवार, अपनी जड़ों और अपने दायित्वों की ओर लौट आता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद ने केवल सामाजिक यथार्थ ही नहीं, पीढ़ियों के मानसिक संक्रमण को भी बड़े यथार्थपूर्ण और संतुलित ढंग से चित्रित किया है; झुनिया, जो अविवाहित माँ बनती है। प्रेमचंद की दृष्टि में केवल 'गिर गई स्त्री' नहीं बल्कि वह स्त्री है जो नए परिवेश में अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाने की ताकत रखती है– धनिया उसे अपनाती है समाज उसे ठुकराता है लेकिन वह अपने जीवन को नया रूप देती है जिससे यह दर्शाया गया है कि प्रेमचंद का स्त्री चित्रण किसी भी दृष्टि से केवल सहनशीलता तक सीमित नहीं बल्कि संघर्षशीलता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है; राय साहब, खन्ना, मालती, मेहता जैसे पात्र शहरी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं– जहाँ संबंधों में बनावटीपन है, नैतिक द्वंद्व हैं, आत्म–विश्लेषण है लेकिन ज़मीन से जुड़ाव नहीं; मालती और मेहता के बीच का दार्शनिक संवाद, खन्ना की व्यावसायिक लोलुपता, राय साहब का खोखला आदर्शवाद – ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आधुनिक भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का संपर्क तो जनता से है पर सहानुभूति नहीं; प्रेमचंद ने इन्हें केवल

सजावट के पात्र नहीं बनाया, बल्कि होरी के समानांतर उनकी जटिलताओं को रखकर यह प्रश्न उठाया है कि क्या केवल गाँव ही बर्बादी के शिकार हैं या नगरों के आत्मविहीन, संबंधविहीन, उद्देश्यहीन जीवन भी उतने ही त्रस्त और दिशाहीन हैं।

गोदान की भाषा सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल है – ग्रामीण पात्रों की भाषा में आंचलिकता और ठेठपन है नगर पात्रों की भाषा में बौद्धिकता और शैलीबद्धता, जिससे पात्रों की सजीवता और अधिक स्पष्ट होती है।

प्रेमचंद का संवाद लेखन इतना जीवंत है कि पाठक उस समय, उस समाज और उस परिस्थिति में स्वयं को खड़ा पाता है – जैसे पंचायत का दृश्य, जहाँ होरी झूठ बोलता है कि झुनिया उसकी बहू है या धनिया और होरी के बीच की तकरारें, जो एक सामान्य ग्रामीण दंपति की झलक देती हैं या मेहता और मालती के बीच का आत्मिक प्रेम–सब कुछ एक बड़े फलक पर भारतीय समाज की बहुरंगी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। गोदान के प्रतीक अत्यंत शक्तिशाली हैं–गाय केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज और किसान की आत्मा का प्रतीक बन जाती है।

गोदान स्वयं केवल मृत्युकालीन धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उस भारतीय किसान की अंतिम इच्छाओं उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसके अधूरे स्वप्नों का प्रतिनिधित्व बन जाता है; प्रेमचंद का यह उपन्यास एक साथ कई विमर्शों को जन्म देता है – जैसे किसान विमर्श, स्त्री विमर्श, वर्ग संघर्ष, धर्म और पाखंड, शहरी बनाम ग्रामीण द्वंद्व, आर्थिक विषमता, राजनीतिक निष्क्रियता और संवेदनात्मक नैतिकता, जिससे यह केवल साहित्यिक रचना नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय दस्तावेज़ बन जाता है।

गोदान को पढ़ रहा पाठक प्रेमचंद को दार्शनिक की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक शल्य चिकित्सक की तरह समाज की नसों को समझ पाता है। प्रेमचंद केवल समस्या नहीं दिखाते, बल्कि उसकी जड़, उसकी परतें और उसके पीछे छिपी असहायता को भी उजागर करते हैं।

यही कारण है कि गोदान केवल 1930 के दशक की कहानी नहीं है, बल्कि आज भी जब कोई किसान आत्महत्या करता है, जब किसी महिला को सामाजिक मर्यादा की दुहाई देकर तिरस्कृत किया जाता है जब शहरों में संबंध खोखले होते हैं, और जब धर्म को केवल पाखंड के रूप में उपयोग किया जाता है तब गोदान की कथाएँ, पात्र और संवाद पुनः प्रासंगिक हो जाती हैं; प्रेमचंद की यह कृति मेरे लिए इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह मुझे केवल साहित्यिक सौंदर्य ही नहीं देती बल्कि यह मेरी संवेदनाओं, मेरे विवेक और मेरे सामाजिक दृष्टिकोण को परिष्कृत करती है– यह मुझे आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती है, यह मुझे यह सोचने पर विवश करती है कि क्या मैं भी उस समाज का हिस्सा हूँ जो होरी को गाय दान तक नहीं करने देता या उस समाज का जो झुनिया को स्वीकार नहीं करता या उस नगर का जो दिखने में उज्ज्वल है लेकिन भीतर से खोखला; यही सवाल बार–बार मुझे गोदान की ओर लौटने को प्रेरित करते हैं – क्योंकि यह पुस्तक हर बार नया दृष्टिकोण देती है, नया अनुभव देती है और नई पीड़ा देती है – जो कहीं न कहीं मुझे मानवीय बनाती है मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाती है और यह बताती है कि साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक नैतिक चुनौती है और एक संवेदनात्मक यात्रा है – और इस संदर्भ में गोदान जैसा उपन्यास मुझे आत्मा की गहराइयों तक प्रभावित करता है उसे झकझोरता है और मेरा प्रिय बन जाता है।

प्रेरणा पीपलानी
ग्राहक सेवा सहयोगी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

मैं नारी हूं

ना पूछो की मैं कौन हूँ ?
मैं सशक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कभी पवन सी अलमस्त मैं, कभी धरा सी परिपक्व हूँ!
मैं जननी हूँ, है सृजन मुझसे, मैं नस–नस में बहता रक्त हूँ;
मैं शोर हूँ, मैं मौन हूँ, मत पूछो मुझसे मैं कौन हूँ?

कभी हूँ मैं सिंह की गर्जना, कभी खुद ही सिंह सवार हूँ;
मैं क्रोध हूँ, और शांत भी, मुझसे ही माँ का प्यार भी ;
मैं धीर हूँ और वीर भी, न समझो की मैं गौण हूँ!

मैं शक्ति का स्वरुप हूँ, मैं भक्ति का अभिरूप हूँ;
मैं ज्ञान हूँ वरदान भी, मैं क्षमा, तप और दान भी;
मैं सृष्टि का आधा अंश हूँ, न समझो की मैं गौण हूँ !

मुझे खुद को अब है जानना, अपने अंतर्मन को पहचानना,
अब मेरा ये संकल्प है, न बचा कोई विकल्प है;
मुझे याद है मैं हूँ सुता, और हूँ किसी की अर्धांगिनी;

है मेरा कोई अंश भी, मुझसे है किसी का वंश भी!
हर रूप मुझे स्वीकार है, पर मेरे कण–कण की ये पुकार है;
मुझे नाम कोई भी दे दो तुम अब सबसे पहले मैं ''मैं'' भी हूँ;

न समझो की मैं गौण हूँ, न पूछो की मैं कौन हूँ,
मैं रवि की लालिमा, सदियों के ताप का नाश हूँ;
ना मैं हारी थी ना हारूंगी, मैं शक्ति सी सशक्त नारी हूँ!!

प्रियंका शर्मा
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
अधिकारी, दुर्गापुरा शाखा

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की गतिविधियाँ

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा शिक्षकों का सम्मान

शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थानीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

इंडियन बैंक की गतिविधियाँ

श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अंचल कार्यालय, इंडियन बैंक, जयपुर को बैंक नराकास, जयपुर का तृतीय पुरस्कार

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर द्वारा इंडियन बैंक, अचल कार्यालय, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राजभाषा उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

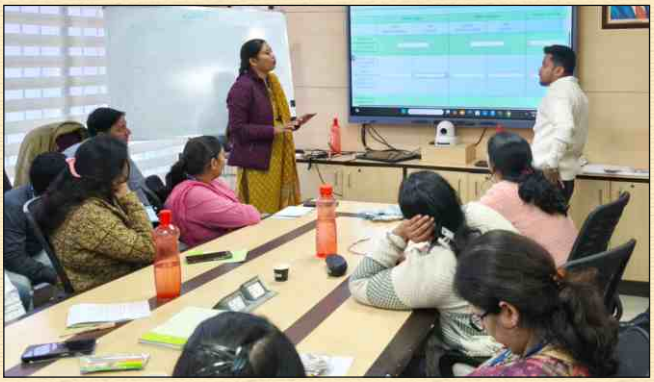

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा अंचलाधीन शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा अधिनियमएवं नियम तथा यूनिकोड टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा हिंदी भाषा ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजाज नगर, जयपुर में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 06 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और प्रेरणा को बढ़ावा देना रहा।

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय का औपचारिक निरीक्षण

उप निदेशक (राभा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री धर्मबीर द्वारा इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर का औपचारिक निरीक्षण दौरा किया गया।

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित।

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा 14.09.2025 से 27.09.2025 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, इस दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय जयपुर – अजमेर

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय जयपुर–अजमेर की दिसंबर तिमाही 2025 की कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी एवं कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुये उप मंडल प्रमुख श्री अनिल कुमार।

प्रश्नोत्तरी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय जयपुर–अजमेर द्वारा बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में उत्कर्ष शिक्षण संस्थान में प्रश्नोत्तरी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मंडल प्रमुख श्री प्रेमचंद बागड़ी ने की।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता

बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय जयपुर–अजमेर द्वारा विवेक टेक्नो स्कूल, जयपुर में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को उप मंडल प्रमुख श्री अनिल कुमार ने पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठं प्रबन्धक (राजभाषा) डॉ. ममता मीना उपस्थित रहीं।

ई–पत्रिका का विमोचन

पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय, जयपुर–अजमेर की दिसंबर तिमाही 2025 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मण्डल की ई–पत्रिका 'पीएनबी रजवाड़ा' का विमोचन मण्डल प्रमुख श्री धर्मेंद्र कुमार, उपमंडल प्रमुख श्री अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे।

राजभाषा समारोह एवं काव्य गोष्ठी आयोजित

पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय जयपुर–अजमेर द्वारा राजभाषा समारोह का अयोजन किय गया। इस अवसर पर सुरक्षा विभाग को विभागीय पुरस्कार प्रदान करते हुए अंचल प्रमुख श्री राजेश भौमिक, उप अंचल प्रमुख श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मण्डल प्रमुख श्री धर्मेंद्र कुमार।

हिन्दी माह का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक मण्डल कार्यालय जयपुर–अजमेर द्वारा हिन्दी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रतिभागी।

सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय प्रमुख	राजभाषा प्रभारी
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, "बड़ौदा भवन" प्लॉट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर–302018	श्री एम अनिल, महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, दूरभाष : 0141–2727101 ई–मेल : zm.rz@bankofbaroda.com	श्री अम्ब्रेश रंजन कुमार, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9634885718, ई–मेल : rajbhasha.rz@bankofbaroda.co.in
2.	पंजाब नैशनल बैंक मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर, द्वितीय तल, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर	श्री धर्मेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8238559749 ई–मेल : coajmraj@pnb.co.in	डॉ ममता मीना, प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8890155809, ई–मेल : coajmraj@pnb.co.in
3.	आंचलिक कार्यालय, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 30–31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड़, विद्युत नगर, अजमेर रोड़, जयपुर–302021	श्री अविनाश कुमार तिवारी, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाषः 8146031913 ई–मेलः zm.jaipur@psb.co.in	श्री सुशील कुमार, प्रबंधक, दूरभाष : 8558849599, 7269990999, ई–मेल : sushil-kumar2@psb.co.in
4.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा, चौथा और पांचवां तल, बीमा भवन, एन बी सी सी सेंटर, लालकोठी स्कीम, सहकार मार्ग, जयपुर	श्री अमृत लाल मीणा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 7665014681 ई–मेलः al.meena@nic.co.in	सुश्री अनुराधा शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 8769678495, ई–मेल : anuradha.sharma@nic.co.in
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, किसान भवन लाल कोठी टोंक रोड जयपुर 302005 राजस्थान	श्री रंजीत कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8898078004 ई–मेल : rh.jaipur@unionbankofindia.bank	श्री कमल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8638731132, ई–मेल : Kamal.kumar@unionbankofindia.bank
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एस बी 57, प्रथम तल, रिद्धि टावर, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री निधिर कान्त, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाषः 7358352009 ई–मेल : jaipurrm@iobnet.co.in	श्रीमती रेणु सरोज, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9166118651, ई–मेल : renusaroj@iobnet.co.in
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम , द्वितीय, कार्मिक विभाग, 5 वां तल, सेक्टर –5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर 382833	दिनेश कुमार तनानिया, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दूरभाषः 0141–2795852 / 9167939815 ई–मेलः sdm.jaipur2@licindia.com	श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 9414340632, ई–मेल : rajendrakumar.6412@gmail.com
8.	भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर	प्रदीप्त किशोर पांडा, उप महाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी, दूरभाष : 0141–2256311 ई–मेल : cdo.lhojai@sbi.co.in	श्री प्रदीप कुमार, मुख्य प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 8527891007, ई–मेल : rajbhasha.lhojai@sbi.co.in
9.	राष्ट्रीय आवास बैंक, NF 01, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री रवि कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 099684 09600 ई–मेल : ravi.singh@nhb.org.in,	सुश्री अपराजिता जैन, प्रबंधक, दूरभाष : 8130492090, ई–मेल : aparajita.jain@nhb.org.in
10.	दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय : द्वितीय तल, टोंक रोड, नेहरू प्लेस, जयपुर–302015	श्री बी. सी. सेठी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 8107477958 ई–मेल : bc.sethi@newindia.co.in,	श्री घनश्याम मीणा, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9868797205, ई–मेल : ghanshyam.meena@newindia.co.in
11.	भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, रामबाग सर्किल, टोंक रोड़, जयपुर – 302004	श्री नवीन नंबियार, क्षेत्रीय निदेशक, दूरभाष : 0141–2577952 ई–मेलः rdjaipur@rbi.org.in	श्री लुईस होरो, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 9746966444, ई–मेल : louishoro@rbi.org.in
12.	आईडीबीआई बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, शोरूम न. 2 एवं 3, सन्नी पैराडाइज, नीलकमल कंपनी के पास, टोंक रोड, जयपुर – 302015	श्री अनुपम पार्थसारथी, महाप्रबंधक, दूरभाषः 9819642551 ई–मेल : anupam.parthasarthi@idbi.co.in	श्री मनोज कुमार राजोरिया, प्रबंधक, दूरभाष : 9799927768, ई–मेल : manoj-rajoria@idbi.co.in
13.	बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय जयपुर, बी 4, सेक्टर – 2, स्टार हाउस, जवाहर नगर, जयपुर	श्री राजेश कुमार सिंह, अंचल प्रबंधक, दूरभाष : 9031077709 ई–मेलः zo.jaipur@bankofindia.co.in	श्री रोहिताश कुमार खरींटा, प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 9829909605, ई–मेल : Jaipur.rajbhasha@bankofindia.co.in
14.	यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय – एनबीसीसी सेंटर सहकार मार्ग ज्योति नगर जयपुर	श्री आलोक कुमार जैन, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 7823987436 ई–मेल : alokjain@uiic.co.in	श्री चेतन अवतार मीना, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 7014882141, ई–मेल : chetanavatar@uiic.co.in

सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय प्रमुख	राजभाषा प्रभारी
15.	बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, "बड़ौदा भवन" प्लॉट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर–302018	श्री देबाशीष बक्शी, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8094018100 ई–मेल : rm.jaipur@bankofbaroda.com	सुश्री नारायणी देवी, प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 8725882677, ई–मेल : rajbhasha.jaipur@bankofbaroda.co.in
16.	यूको बैंक, अंचल कार्यालय जयपुर ऑर्बिट मॉल द्वितीय तल जयपुर	श्री राजेश कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412226155 ई–मेल : zojaipur.ol@ucobank.co.in	श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 7696386540, ई–मेल : zojaipur.ol@uco.bank.in zo.jaipur@uco.bank.in
17.	भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जयपुर, ए–5 नेहरू प्लेस,जयपुर–302015	श्री प्राणेश प्रशांत, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141 2745351 ई–मेल : dgm.zojai@sbi.co.in	श्री नीरज शर्मा, प्रबंधक, दूरभाष : 8527600366, ई–मेल : neeraj.sharma45@sbi.co.in
18.	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय जयपुर, 6टा तल, फॉर्च्यून हॉइट्स, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम, जयपुर राजस्थान 380001	श्री प्रशांत कुमार राजू, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141 2379904 ई–मेल : zmjaipur@mahabank.co.in	सुश्री रश्मि शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8770610600, ई–मेल : hindi_jai@mahabank.co.in
19.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, प्रथम तल, एल आई सी कॉप्लेक्स भवानी सिंह मार्ग जयपुर 302005	श्री भानू प्रकाश वर्मा, महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412946039 ई–मेल : rojaipur@sidbi.in	श्री वेद मखीजा, सहायक महाप्रबंधक (हिंदी), दूरभाष : 8764064618, ई–मेल : Vedmakhija@sidbi.in
20.	केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक, दूरभाष : 8334993838 ई–मेल : jaipurco@canarabank.com	श्री रवि प्रकाश मीना, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9414553531, ई–मेल : raviprakashm@canarabank.com
21.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, 3, नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर	डॉ. आर. रवि बाबू, मुख्य महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141–2740821 ई–मेल : jaipur@nabard.org	श्री अरविंद पारीक, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 9829972282, arvind.pareek@nabard.org सुश्री निवेदिता तिवारी, प्रबंधक, मो. 8604621301
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, द्वितीय तल, ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	श्री विपिन कुमार शुक्ला, महाप्रबंधक, दूरभाष : 9619015063 ई–मेल : fgm.jaipur@unionbankofindia.bank	सुश्री सोनिया चौधरी, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9560622690, ई–मेल : Sonia.choudhary@unionbankofindia.bank
23.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आनंद भवन प्रथम तल संसार चंद्र रोड जयपुर	श्री शैलेश वर्मा, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 9792068555 ई–मेल : rmjaipro@centralbank.co.in	सुश्री रानू साव बैरवा, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 6295561377, ई–मेल : hindijaipro@centralbank.co.in
24.	पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय जयपुर, पीएनबी हाउस, 2 नेहरू प्लेस, चतुर्थ तल, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री राजेश भौमिक, महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141–2743349 ई–मेल : zojaipur@pnb.co.in	श्री अजय सक्सेना, वरिष्ठ प्रबंधक–राजभाषा, दूरभाष : 9828288093, ई–मेल : zojprraj@pnb.co.in
25.	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय 1, जीवन प्रकाश, भवानी सिंह मार्ग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर–302005	श्री संजय कुमार, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दूरभाष : 0141–2747081 ई–मेल : sdm.jaipur@licindia.com	श्रीमती नीता शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 9783818986, ई–मेल : pir.jaipur@licindia.com
26.	दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 9वां, और 10वां तल, एनबीसीसी बिल्डिंग, बीमा भवन, सहकार मार्ग, जयपुर	श्री संजय जैन, उप महाप्रबंधक, दूरभाष: 0141–2850441 ई–मेल : sanjayjain@orientalinsurance.co.in	श्री नेमी चंद मीना, उप प्रबन्धक, दूरभाष : 9462809080, ई–मेल : nc.meena@orientalinsurance.co.in
27.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, दायाँ भाग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानी सिंह रोड, जयपुर –302005,	श्री शत्रुघ्न प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 0141–2852150 / 9411393141 ई–मेल : shatrughanp@aicofindia.com	सुश्री श्रीप्रभा सैनी, उप प्रबंधक, दूरभाष : 8073384001, ई–मेल : shriprabhas@aicofindia.com
28.	केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, केनरा बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	श्री बी. श्रीनिवास, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412220247 ई–मेल : b.srinivas@canarabank.com	श्री रवि प्रकाश मीना, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9414553531, ई–मेल : raviprakashm@canarabank.com
29.	इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर	श्री मिथिलेश कुमार, अंचल प्रबंधक, दूरभाष: 01412752216, मो: 9873765099 ई–मेल: zo.jaipur@indianbank.co.in	सुश्री निशा चोरेटिया, प्रबन्धक, दूरभाष : 8583911005, ई–मेल : nisha.chauretiya@indianbank.co.in

बैंक नराकास जयपुर के सदस्य कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

AIC
भारतीय कृषि बीमा कंपनी
AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

नाबार्ड
NABARD

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

SBI

इंडियन बैंक
इलाहाबाद
Indian Bank
ALLAHABAD

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

pnb

केनरा बैंक
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

IDBI BANK

सिडबी
sidbi

यूनाइटेड इंडिया
UNITED INDIA

यूको बैंक
UCO BANK

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

The New India Assurance Co. Ltd
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance
National Insurance Company Limited